



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 1993/फाल्गुन 10, 1914
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1993/PHALGUNA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1993

फा. सं. 15 (46) - बी (डी) 93 :- निम्नलिखित
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

बजट 1993-94 वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह का
भाषण

27 फरवरी, 1993

भाग 'क'

महोदय

मैं वर्ष 1993-94 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. हमारी सरकार को कार्यभार संभाले अब 20 महीने
हो गए हैं : ऐसे 20 घटनापूर्ण महीने जिनमें हमने विरासत

में मिली अत्यंत कठिन आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के लिए
लगातार काम किया है। जून, 1991 में अर्थ-व्यवस्था भुगतान
संतुलन के अपूर्व संकट में फंसी हुई थी। आयातों पर एक
झूर बनाव लगाया गया था; अंतर्राष्ट्रीय विश्वास लड़खड़ा
गया था; औद्योगिक उत्पादन गिर रहा था; और मुद्रा-
स्फीति बढ़ रही थी।

3. संकट की अनुभूति अब हमारे पीछे रह गई है।
हमने अपने विदेशी भुगतानों के संबंध में सामान्य स्थिति
को बहाल कर दिया है। अगस्त 1991 में मुद्रास्फीति की
वार्षिक दर 17 प्रतिशत के शीर्ष पर थी उसे घटाकर 7
प्रतिशत से कम कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वास
बहाल कर दिया गया है। चालू वर्ष में कृषि का अच्छा
निष्पादन रहा है और औद्योगिक उत्पादन भी पूर्व स्थिति
में आना शुरू हो गया है। अर्थ व्यवस्था की संवृद्धि जो वर्ष
1991-92 में गिरकर 1.2 प्रतिशत हो गई थी उसके
वर्ष 1992-93 में लगभग 4 प्रतिशत हो जाने की प्रत्याशा

1. राजकोषीय अनुशासन और आंचागत सुधार के दो जुड़वाँ तथ्यों पर आधारित होने वाली जिस आर्थिक कार्यनीति पर मैं चल रहे हैं वह उससे 20 निष्पत्तिक आधार द्वारा उचित पद्धत हुई है।

4. आर्थिक अनुशासन जल्दी था, क्योंकि सरकार बहुत जल्द संयम से अपने बाधनों से अधिक खर्च करती रही थी। न्दीय सरकार के बहुत दुरे राजकोषीय घाटे हमारी भुगतान तुलन संबंधी समस्या बढ़ती हुई कीकड़ी और उच्च व्याज रों का मूल कारण थे। वर्ष 1980-81 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को चालू वर्ष घटाकर लगभग 5 प्रतिशत पर लाकर हमने अच्छी प्रगति की

5. संसाधन के प्रयोग में दक्षता वृद्धि तथा हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धित्वता में सुधार करने के उद्देश्य की अत्यंत सुधार नीतियां भुगतान के संकट का चिरस्थायी समाधान प्रदान करने में निष्पत्तिक रही हैं। हमारी व्यवहार और औद्योगिक नीतियों की पुनः संरचना करना, बहुत घरेलू प्रतिस्पर्धी के माध्यम से दक्षता को प्रोत्साहित करना, अल्प-उत्पादकों को शुल्क की समुचित दरों पर आयात करने की स्थिति में लाना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना तथा औद्योगिकी का उन्नयन और प्रगामी रूप से भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना जारी था। इन सुधारों के बिना भारत को 21वीं शताब्दी में एशिया के लगभग सबसे गरीब देश के रूप में प्रवेश करने वाले देश के एक निश्चित परिदृश्य का सामना करना पड़ेगा। जो विश्वास है कि भारतीय लोग ऐसे परिणाम को कभी हन नहीं करेंगे। भारत के प्राकृतिक और मानव संसाधन में विश्व अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख शक्ति केन्द्र होने के रूप में सोचने का हकदार बनाते हैं। हमारे सुधार ठीक इसी दर्शन से प्रेरित होते हैं।

6. हमने जो नीतियां अपनाई हैं वे किसी भी तरह से परीशों और सुविधावर्धित लोगों का ध्यान रखने की हमारी समनवृद्धता को कम नहीं करती है। इसके विपरीत हमने परीशों और कामकाजी वर्गों पर समायोजन के भार को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए हैं। हमने अर्थकार के उन व्यवसायिक भविष्यवक्ताओं को गति प्रदान कर दिया है, जो लाखों लोगों के बेरोजगार हो जाने की भविष्यवाणियां कर रहे थे।

7. अब हमने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, जब हम यह जानते थे कि हमारी नीतियों का लाभ तीन-चार वर्षों के बाद ही दिखाई देगा। इस लिए धैर्य अनिवार्य है। फिर भी, माननीय सचिव इस बात से संतोष प्राप्त कर सकते हैं कि प्रारम्भिक परिणाम निश्चित रूप से उत्साहजनक हैं। मुद्रास्फीति घटी है और उत्पादन पूर्व स्थिति की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। उद्योगों के परिणामस्वरूप आयातों से बच जाने के हमारे भय अत्यधिक अतिरिक्त सिद्ध हुए हैं।

वर्ष 1992-93 में आयात लाइसेंस की प्रणाली की वास्तविक स्थापना के बावजूद भी वर्ष 1992-93 में अमरीकी डालर में किए गए कुछ आयातों के वर्ष 1990-91 के कुल आयातों से कम रहने की संभावना है। यद्यपि, अधिकांश चालू लेखा लेन-देनों के लिए रुपया चलिया गया है, बाजारवित्तिय दर अपेक्षाकृत स्थिर रही है। निवेश के बर्ताव में पर्याप्त सुधार हुआ है। गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा निर्मित पूंजी निर्गम अप्रैल-अक्तूबर 1992 में पिछले वर्ष की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक थे। वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1992-93 के प्रथम दस महीनों में स्वीकृत किए गए उधार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 49 प्रतिशत अधिक थे। विदेशी निवेशक विजली तथा पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों सहित बहुत से क्षेत्रों में निवेश करने में सक्रिय रुचि दिखा रहे हैं। अक्टूबर 1991 में जनवरी के अन्त तक विदेशी निवेश प्रस्ताव के लिए दिए गए अनु-मोदनों की राशि 2.3 बिलियन अमरीकी डालर के इक्विटी निवेश के बराबर है। वस्तुतः यह इस चरण पर केवल अनुमोदन है और वास्तविक धन प्रवाहों के कार्यान्वित होने में समय लगेगा, लेकिन वे निश्चित रूप से भविष्य में भारी मात्रा में निवेश के अन्तः प्रवाहों की पर्याप्त क्षमता का संकेत देते हैं।

8. फंड भी आत्मसंतोष के लिए कोई स्थान नहीं हैं। राजकोषीय असंतुलन अभी भी बड़े हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता और उनकी संसाधन सृजन करने की क्षमता अभी भी बहुत अपर्याप्त है। मुद्रास्फीति की आशंकाओं को अभी भी अर्थव्यवस्था से निष्कासित नहीं किया गया है और यदि राजकोषीय अनुशासन में स्थिरता लाई गई तो मुद्रास्फीति का दबाव सरलता से दुबारा बन सकता है। अर्थव्यवस्था अभी भी बाहरी आघातों और विश्वास से अभाव के प्रति कमजोर है। दिसम्बर और जनवरी में हुए दंगों और उपद्रवों ने भी घरेलू उत्पादन और निर्यातों में गति-रोध पैदा करके हमारे राजतंत्र और समाज की स्थिरता और आर्थिक सुधार के कठिन कार्य को बनाए रखने के हमारे इरादे के प्रति संदेह उत्पन्न कर चोट पहुंचाई है। हम ऐसे संदेहों को सहन नहीं कर सकते।

9. हमारी आर्थिक पुनःसंरचना की इस महत्वपूर्ण अवस्था में आर्थिक नीति के लिए प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं :

— यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीतिकारी संभावनाएं प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित हों हमें राजकोषीय सुधार को अवश्य जारी रखना चाहिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों में ही राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष ही और अधिक कम करना चाहिए।

— पिछले दो वर्षों के दौरान व्यय को सीमित रख-कर, राजकोषीय कौशल के लिए बनाई गई गुंजाइश को विशेष रूप से गरीबी-उन्मूलन, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा

एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1993-94 में विकास व्यय को एक सशक्त प्रोत्साहन देने के लिए अवश्य प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

— अनिश्चित औद्योगिक पुनरुत्थान को वर्ष 1993-94 में एक मजबूत पुनरुद्धार के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए जिसके बाद आठवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों में एक सशक्त तेजी लाई जा सकती है।

— हमें कर सुधार की अपनी घोषित कार्यनीति के संबंध में और अधिक प्रगति कर सरल कर प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें कर-दर माध्यम हों तथा करों की वसूली पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए।

— हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आर्थिक कार्यनीति कृषि को पूर्ण समर्थन दे, जिस पर हमारे अधिकांश लोगों की जीविका और कल्याण निर्भर है; और कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों, जिनमें रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि करने की भारी क्षमता है, को भी समर्थन देना चाहिए।

— अंततः, निर्यातों की वास्तविक उच्च प्राथमिकता वाला एक राष्ट्रीय प्रयास बनना चाहिए, ताकि विदेशों से विशेष वित्तपोषण की आवश्यकता को जारी रखे बिना हम भुगतान-संतुलन पर यथासंभव शीघ्रता से काबू पा लें। आत्म-निर्भरता के लिए यही एकमात्र अर्थपूर्ण मार्ग है।

10. वर्ष 1993-94 के लिए ध्यय तथा कर प्रस्तावों, जिन्हें मैं शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगा, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए हैं।

11. इस वर्ष के कमजोर औद्योगिक पुनरुत्थान को अगले वर्ष एक सशक्त पुनरुद्धार में परिवर्तित करने के लिए समुचित ब्याज दरों पर ऋण की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण की अपर्याप्तता के पीछे एक कारक सरकार द्वारा ब्याज की बाजार दरों से कम दरों पर सांविधिक नकदी अनुपात (एस.एल.आर.) के माध्यम से बैंकों के अधिकांश संसाधनों का पूर्वक्रयाधिकार है। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उधार देने हेतु संसाधनों की बड़ी मांग जारी करने की दृष्टि से हमने 1992-93 में सांविधिक नकदी अनुपात को कम करने की प्रक्रिया आरंभ की है। हमारा उद्देश्य अगले 3 वर्षों में सांविधिक नकदी अनुपात इस समय के लगभग 36 प्रतिशत के प्रभावी औसत स्तर को और कम करके लगभग 25 प्रतिशत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक उभरती हुई कुल मौद्रिक एवं ऋण स्थिति को ध्यान में रखकर उचित कमी को सुनिश्चित चरणबद्धता को घोषित करेगा।

12. मुद्रास्फीति में अभी तक प्राप्त की गई कमी ब्याज दरों में कमी करने को उचित ठहराती है। तदनुसार,

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक जमा राशियों पर अधिकतम ब्याज दर को 12 प्रतिशत से 11 प्रतिशत करने संबंधी कमी को अलग से अधिसूचित कर रहा है। इसके साथ-साथ वाणिज्यिक अग्रिमों पर उधार देने की 18 प्रतिशत की न्यूनतम दर को कम करके 17 प्रतिशत किया जा रहा है। मेरी यह आशा है कि ब्याज दरों में कमी करने से आगामी वर्ष में आर्थिक पुनरुत्थान में सहायता मिलेगी। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति में कमी आएगी, ब्याज की दरों में आगे कमी करने की गुंजाइश होगी।

13. हमारे देश में कोई भी ऐसी आर्थिक नीति सफल नहीं हो सकती जो व्यापक आधार वाले और न्यायसंगत विकास के समर्थन देने में कृषि की केन्द्रीय भूमिका को स्वीकार नहीं करती हो। सरकार आर्थिक नीति तैयार करने में कृषि, कृषि-प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से बचनबद्ध है।

14. कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और इसे लाभकारी बनाने का एक प्रमुख साधन किसानों को, लाभकारी कीमतें प्रदान करने का आश्वासन देना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को, निविष्टियों की लागत में हुई वृद्धियों की तुलना में प्रतिपूर्ति भी की जाए, पिछली खरीफ फसल और आगामी रबी फसल के लिए वसूली मूल्यों में काफी अच्छी वृद्धि की गई है। सरकार की यह भी नीति है कि देश के भीतर कृषि-उत्पादों के संचलनों पर प्रशासनिक प्रतिबंध न लगाए जाएं। हमारे किसानों को घरेलू बाजार में उपलब्ध मूल्यों का पूर्ण लाभ अवश्य मिलना चाहिए।

15. कृषि ऋण, कृषि और मोटे तौर पर ग्रामीण विकास के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण निविष्ट है। संस्थागत स्रोतों से ग्रामीण ऋण के प्रवाह के वर्ष 1992-93 में 13,800 करोड़ रुपये से बढ़कर 1993-94 में 16,500 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है, जो कि 20 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। बैंकों को नाबाई की निवेश पुनर्वित्त सहायता में 22 प्रतिशत की वृद्धि होने से यह चालू वर्ष में 2300 करोड़ रुपये से, 1993-94 में 2800 करोड़ रुपये हो जाएगी। इर सीमाओं के अंतर्गत, नाबाई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए नवीन एकमुश्त उपाय किए हैं। लघु सिंचाई के लिए मियादी उधारों से 3.75 लाख कुओं की खुदाई और 6 लाख पम्प सेट लगा ने में सहायता मिली। बैंक उधारों के नाबाई पुनर्वित्तपोषण की दर को उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत तक और कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों की शतप्रतिशत निर्यातोमुखी इकाइयों के निवेश के संबंध में भी इसकी वृद्धि की जा रही है। नाबाई 125 करोड़ रुपये के परिधाय से पांच चुने हुए जिलों में ग्रामीण उद्योगों के सघन विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करेगा। नाबाई

कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में नवीन निवेशों की सहायता के 5 करोड़ रुपये के आरम्भिक संग्रहण से एक उच्च पूंजी निधि और सहकारी बैंकों में प्रबंध प्रणालियों और दक्षताओं को सुधार में सहायता देने के लिए 10 करोड़ रुपये के आरम्भिक संग्रहण से एक सहकारी विकास निधि की स्थापना करने जा रहा है। वर्ष 1993-94 में हम कृषि ऋण प्रणाली को फिर से मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देंगे ताकि यह पूंजी निर्माण और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का एक अधिक कारगर साधन बन सके।

16. भारतीय उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के उच्च स्तरों को धीरे-धीरे कम करने और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने की हमारी कार्यनीति से भारतीय कृषि को स्पष्ट रूप से सहायता मिलेगी। इससे उच्च औद्योगिक कीमतें, जो किसान को बेनी पड़ती हैं, कम होंगी। इससे एक अधिक प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दर सुनिश्चित होगी, जिससे हमारे कृषि और कृषि-आधारित निर्यात अधिकाधिक लाभकारी होंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि मध्याह्न में ये परिवर्तन विशेष आर्थिक सहायताओं के किसी कार्यक्रम की तुलना में कृषि उत्पादकों की सहायता करने में अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

17. पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण के दौरान मैंने संकेत दिया था कि सरकार वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए गठित नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित करना चाहती है। प्रतिभूति कोटाले, जिसका अप्रैल, 1992 में पता चला था, ने कुछ कमियाँ उजागर की हैं, जिन्होंने वित्तीय क्षेत्र में सुधार की जरूरत को अत्यावश्यक बना दिया है। पिछले वर्ष आरम्भ किया गया एक प्रमुख सुधार आय की पहचान के लिए मानदण्ड शुरू करना और इसे हुए ऋणों के लिए व्यवस्था करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारी गई बासले समिति मानदण्डों के अनुरूप नई पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का निर्धारण करना था। इन नए मानदण्डों से यह सुनिश्चित होगा कि बैंकों की बहियाँ उनकी वित्तीय स्थिति को अधिक विणुद्ध रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारी गई लेखाकरण प्रणालियों के अनुसार प्रदर्शित करेंगी। इन परिवर्तनों से बैंकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने की हमारी दक्षता में सुधार होगा और इससे बैंकों का पर्यवेक्षण भी अधिक कारगर होगा।

18. तथापि, नए मानदण्डों के कारण बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में डूबे हुए और संदिग्ध ऋणों के लिए 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि के लिए बड़े प्रावधान करने होंगे। बैंकिंग प्रावधान संबंधी मानदण्डों के चरणों में आरम्भ किए गए हैं, इसलिए पहला प्रभाव 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुभव किया जाएगा और इससे आगे प्रभाव अगले वर्ष दिखाई देगा। परिणामी हानियाँ बैंकों की पूंजी, जो नई पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के रहते हुए

इसके ही अर्थात् है, को समाप्त प्रायः कर देगी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की व्यवहार्यता और वित्तीय स्थिति की सुरक्षा करने के लिए प्रावधान मानदण्डों के प्रथम चरण को लागू करने से उत्पन्न अन्तर को पूरा करने हेतु मैं 1993-94 में राष्ट्रीयकृत बैंकों को 5700 करोड़ रुपये की विशाल पूंजी के अंशदान के लिए प्रावधान कर रहा हूँ। बजट से तत्काल कोई निवृत्त बहिर्गमन नहीं होगा, क्योंकि सरकार का अंशदान सरकारी बांडों के रूप में होगा; लेकिन इन बांडों पर व्याज अदायगी और उनके अंततः विमोचन से भविष्य में बजट पर वास्तविक भार आएगा। यह कीमत हमें बैंकों में दीर्घकाल से सहन की जा रही प्रबंध संबंधी प्रणालियों और उधार देने की किस्मों, जिन्होंने पोर्टफोलियो गुणवत्ता और वसूलियों पर अपर्याप्त ध्यान दिया, के कारण चुकानी पड़ रही है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि बैंकों को इतनी भारी मक्का में पूंजी देते समय प्रत्येक बैंक से विशिष्ट वचनबद्धताएं अपेक्षित होंगी कि उनकी भावी प्रबंध पद्धतियाँ पोर्टफोलियो गुणवत्ता का एक उच्च स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करेंगी ताकि यह समस्या फिर उत्पन्न न हो।

19. बड़ी मात्रा में पूंजी प्रदाय करने से भी केवल तात्कालिक समस्या का निदान होगा। अगले वर्ष प्रावधान के दूसरे चरण के कारण अतिरिक्त हानियाँ उत्पन्न होंगी। इसके अलावा पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं भी चरणबद्ध तरीके से आरम्भ की जा रही हैं और इसके कारण वर्ष 1994-95 और वर्ष 1995-96 में अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी। इस भार को अकेले बजट द्वारा दुर्लभ संसाधनों, जो विकास, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, को हानि पहुंचाए बिना वहन नहीं किया जा सकता। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जो ऐसा करने की स्थिति में हैं, अगले तीन वर्षों के दौरान पूंजी आवश्यकताओं में उनकी कमी को पूरा करने के लिए उन्हें नई इक्विटी जुटाने हेतु पूंजी बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी हमारे बैंकों को उनके उधारों के विस्तार में सहायता करेगी अन्यथा जिसमें पूंजी अपर्याप्तता के कारण बाधा पड़ती। सरकार अपने अधिकार स्वाभित्व को जारी रखेगी और इसलिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखेगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए इस वर्ष बाद में आवश्यक विधान बनाया जाएगा।

20. यदि बैंकों को डूबने वाले ऋणों के लिए प्रावधान करने हैं, तब उन्हें अपने डूबने वाले ऋणों पर प्रतिभूतियाँ भी अवश्य वसूलने के योग्य बनाना चाहिए। इस समय बैंक देवताएं वसूल करने की कानूनी प्रक्रिया बड़ी कठिनाई है और न्यायालयों में मामले वर्षों तक चलते रहने हैं। इसलिए, सरकार ने विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि वसूलियाँ करने के लिए बैंक कानूनी कार्यवाई की श्रुता से कर सकें। इस पर अमल करने के लिए विधान इस वर्ष के दौरान लागू कर दिया जाएगा।

21. प्रतिभूति घोटाले ने बैंकों के पर्यवेक्षण की मौजूदा प्रणाली में कमजोरियों को भी उजागर किया है। नरसिम्हम समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पर्यवेक्षणीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में ही एक पृथक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है।

22. बैंकिंग प्रणाली में सुधार के साथ-साथ हम पूंजी बाजारों में सुधार करने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि निवेशक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से बनाए गए उपयुक्त नियमों और विनियमों के अधीन व्यापार और निपटान तीव्रता और पारदर्शिता के साथ हों। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, जिसे बारह महीने पूर्व सांविधिक हैसियत और अधिकार प्रदान किए गए थे, को यह परिवर्तन लाने का कार्य सौंपा गया है। मेरे पिछले वजट भाषण में जैसा वचन दिया गया था, वित्त मंत्रालय में पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय समाप्त कर दिया गया है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के अधीन लगभग सभी अधिकार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को प्रत्यायोजित अथवा अन्तर्गत कर दिए गए हैं।

23. पूंजी बाजार में सुधार करने के लिए चालू वर्ष में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अंतरंग व्यापार (इन्साइडर ट्रेडिंग), म्यूचुअल फंडों के प्रचालन, दलालों के पंजीकरण, मर्चेन्ट बैंकों और अन्य माध्यमों से निपटने के लिए नियम और विनियम अधिसूचित किए गए हैं। मेरे पिछले वजट भाषण में, पूंजी बाजारों में निवेश करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति देने की घोषित योजना कार्यान्वित कर दी गई है और कई अनुमोदन दिए गए हैं। निजी क्षेत्र के कई म्यूचुअल फंडों को हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए एक कंपनी संस्थापित की गई है, जिससे आदर्श स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करने की आशा है। देश भर में दलाल इसके सदस्य होंगे, जो आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं के माध्यम से देश भर में व्यापार करेंगे। राष्ट्रीय स्वीकृति और निपटान प्रणाली सहित एक केन्द्रीकृत आगार की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

24. हम यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प हैं कि पूंजी बाजार में वर्ष 1993-94 के दौरान और अधिक सुधार कार्यान्वित किए जाएं, ताकि पूंजी बाजार निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में निधियां जुटा सकें। प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उसे अतिरिक्त अधिकार देने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम को संशोधित करने का निर्णय किया है।

25. बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजारों में चल रहे सुधारों के साथ-साथ वीमा उद्योग में ऐसे ही सुधारों की आवश्यकता पर बल देना जरूरी है जिसका उद्देश्य विनियमों

और पर्यवेक्षण के अधीन एक अधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाना है। मैं इन मामलों की गहराई से जांच करने और छः महीने के भीतर इसकी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

26. मैंने पिछले वर्ष अपने वजट भाषण में विनियम दर प्रबंध की एक नई प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके अधीन एक दोहरी विनियम दर व्यवस्था शुरू की गई थी और पूंजीगत वस्तुओं की अधिकांश मर्दों, कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा सघटकों पर आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। बाजार में विदेशी मुद्रा की खरीद से ये मर्द मुक्त रूप से आयात योग्य हो गई थी। इस प्रणाली ने काफी सुचारु रूप से कार्य किया है और बाजार विनियम दर असाधारण रूप से स्थिर रही है। फिर भी, दोहरे दर का अस्तित्व निर्यातकों और अन्य विदेशी मुद्रा अर्जकों को नुकसान पहुंचाता है, जिन्हें अपनी कमाई का 40 प्रतिशत भाग सरकारी दर के अनुसार अभ्यर्पित करना होता है और वे केवल 60 प्रतिशत पर ही उच्च बाजार दरों का लाभ प्राप्त करते हैं। कई निर्यातकों का कथन है कि यह वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातकों पर कर लगने के समतुल्य हो जाता है, जिसे ऐसे समय जारी रखने का औचित्य नहीं हो सकता जब निर्यात को हमारा पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में दम है और पिछले वर्ष का अनुभव इस विश्वास के लिए आधार प्रदान करता है कि हम विनियम दरों को एक कर सकते हैं और तब भी विनियम दर में स्थिरता के उचित स्तर के साथ भुगतान-संतुलन को बनाए रख सकते हैं। इसलिए सरकार ने दोहरी दर व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय किया है। सभी निर्यातकों तथा साथ ही विदेशों में हमारे कामगारों जैसे अन्य विदेशी मुद्रा अर्जकों को अब इससे बाद अपनी कमाई को बाजार दर पर शत-प्रतिशत परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। अब इसके बाद सभी आयातों के लिए बाजार दर पर भुगतान करना होगा। नई प्रणाली के ब्यौरे अलग से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह निर्यातों को विशेष बड़ोतरी प्रदान करेगी और आगे चलकर यह विदेशी मुद्रा के सरकारी माध्यमों की ओर प्रवाह को प्रोत्साहित करेगी।

27. निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं वाणिज्य मंत्रालय यथासंभव अतिरिक्त निर्यात प्रतिबंधों को दूर करने की दृष्टि से उन मर्दों की सूची को समीक्षा कर रहा है, जिनके निर्यात पर कोई न कोई प्रतिबंध लगा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि निर्यातों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध रहेंगे। भारतीय बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है कि निर्यात ऋणों की मात्रा उनके कुल अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत हों। स्पष्ट निर्यात ऋण पर ब्याज दर को एक प्रतिशत बिंदु तक

कम किया जा रहा है। निर्यातों को समर्थन प्रदान करने के अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्यात ऋण के मामले में व्याज दर को छोड़ दिया जाएगा। जब मैं बजट में कर प्रस्तावों की चर्चा करूंगा तब मैं निर्यातकों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के संबंध में और कुछ कहना चाहूंगा।

28. विदेशी निवेश के संबंध में एक नई नीति, अर्थ-व्यवस्था को आधुनिकीकरण करने और विश्वव्यापी गठबंधन स्थापित करने की हमारी कार्य नीति का अभिन्न अंग रही है, जो उभर रही विश्व अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र में अब तक किए गए नए प्रयासों के उत्साहबर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्यों-ज्यों हमारे सुधार आगे बढ़ेंगे और उनमें गति आएगी, हम निजी निवेश के उस काफी बड़े हिस्से को आकर्षित करने की आशा कर सकते हैं जो भीजुदा तीर पर एशिया में अनेक विकास-शील देशों की ओर प्रवाहित हो रहा है। सरकार ने बहु-पक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एम.आई.जी.ए.) समझौते (कनवेंशन) पर हस्ताक्षर किए हैं और सदस्यता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होते ही हमारे एम.आई.जी.ए. में औपचारिक तौर पर शामिल होने की संभावना है। यू.के., जर्मनी और अमरीका सहित अनेक देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर करने में रुचि दिखाई है। सरकार ने इस मामले में द्विपक्षीय वार्ताओं में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।

29. औद्योगिक आधुनिकीकरण और विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों के सृजन के लिए आधारभूत ढांचे में भारी विस्तार और गुणवत्तात्मक सुधार की आवश्यकता है। यह विद्युत, उत्पादन, दूरसंचार और सड़कों के मामले में विशेष रूप से सत्य है। परंपरागत रूप से ये क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के परिचित उद्योग रहे हैं। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश का पर्याप्त विस्तार निश्चित रूप से आवश्यक है। लेकिन देश की आवश्यकताएं ऐसी हैं, जिन्हें उपयुक्त समय सीमा में पूरा करना सरकारी क्षेत्र की क्षमता से काफी बाहर है। इसलिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की पूर्ति करने के उद्देश्यों से इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी और सहभागिता को प्रोत्साहित करने की एक नीति अपनाई है। ऐसा निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियों, कार्यविधियों और इन क्षेत्रों के विनियमनकारी ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। सरकार का आवश्यकता के अनुसार ऐसे परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

30. पिछले दो वर्षों के दौरान, आर्थिक क्रियाकलापों में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं, ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जिसमें हमारे देशवासियों की शक्ति का प्रयोग नवीकरण, उत्पादन तथा विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तथापि, मुझे यह लगातार बताया जा रहा है कि नीति स्तर पर किए गए

उदासीकरण के बावजूद बहुत से क्षेत्रों में हमारी कार्यप्रणालियां पुरानी हैं और बाधाएं डालने वाली हैं। हमारे बहुत से कानूनों को छत्रते हुए नए आर्थिक वातावरण के अनुसार ढालने के लिए उम की पूरी तरह से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक मंत्रालय में एक विशेष समीक्षा दल गठित किया जाएगा जो नई नीतियों के संदर्भ में परिवर्तनों की संभावनाओं का प्रता लगाने के लिए मौजूदा कानूनों और कार्यप्रणालियों की समीक्षा करेंगे। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से ऐसे ही कदम उठाएंगी क्योंकि उन्हें नए वातावरण में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के कार्य में सहत्वपूर्ण भूमिका भूदा करनी है।

31. अब मैं वर्ष 1992-93 के लिए संशोधित अनुमानों की ओर आता हूं।

32. हमने व्यय पर कठोर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन बजट अनुमानों में कुछ वृद्धियां करना अपरिहार्य था। खाद्य, उर्वरक और निर्यात आर्थिक सहायताओं के संबंध में 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा है। खाद्य आर्थिक सहायता के लिए अतिरिक्त आवश्यकता उच्च वसूली मूल्यों के प्रभाव को समाहित करने के लिए निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने में विलम्ब के कारण है। निर्यात आर्थिक सहायता के लिए अधिक प्रावधान, नकद प्रतिपूरक सहायता और माने गए निर्यातों के लिए लाभों की निरंतरता के संबंध में प्रक्रियाधीन दावों के निपटान के कारण है। उर्वरकों के संबंध में वृद्धि यूरिया के मूल्यों में कमी और उच्चतर निविष्टि लागतों के कारण है। इसके अतिरिक्त मैंने किसानों हेतु उन उर्वरकों की खरीद के लिए 340 करोड़ रुपये की एक-बार की सहायता के रूप में प्रावधान किया है, जिनके मूल्य विनियमित किए गए थे। देश के कुछ हिस्सों में गड़बड़ी की स्थितियों में सुरक्षा से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करानी पड़ी हैं। जबकि वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा रहा है, मैंने इस समय संशोधित अनुमानों में 285 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त प्रावधान शामिल किया है। यदि आगे और प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है, तब हम आवश्यक पूरक अनुदानों के लिए सदन में उपस्थित होंगे। इन अनुदानों तथा अन्य वृद्धियों को, लघु बचतों के संग्रहण के आधार पर राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों की आवश्यकताओं में 1300 करोड़ रुपये की कटौती करके प्रतिसंतुलित कर लिया गया है। लघु बचतों के संग्रहण में गिरावट आना चिंता का विषय रहा है तथा निवेशकों को मिलने वाले प्रतिफल की दर में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इसके फलस्वरूप हाल ही के महीनों में बचतों के संग्रहण में वृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई दी है। इन सब स्थितियों के परिणामस्वरूप कुल आयोजना-भिन्न व्यय में 3278 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

32. आयोजना पक्ष में, कुछ क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय योजना हेतु बजटीय सहायता में वृद्धि की गई। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए 630 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई; यह निधि आर्थिक सुधारों संबंधी हमारी कार्य नीति का प्रमुख अवयव है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया। ग्रामीण विकास के लिए प्रावधान की राशि में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है।

34. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं विशेष रूप से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 1228 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है जहां इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को देखते हुए बजट अनुमानों में किए गए प्रावधान की तुलना में अधिक राशि का आबंटन किया जाना न्यायसंगत है।

35. आयोजना और आयोजना-भिन्न दोनों प्रकार के व्यय को मिलाकर, संशोधित अनुमानों में कुल 1,24,726 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है जब कि बजट अनुमानों में यह राशि 1,19,087 करोड़ रुपए थी।

36. इन अतिरिक्त व्ययों की तुलना में, बेहतर संग्रहण और अपतटीय कच्चे तेल पर मिलने वाली उच्च रायल्टी के कारण राजस्व प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई है। बाजार ऋणों तथा लघु बचत प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां बजट अनुमानों में की गई व्यवस्थाओं की तुलना में कम हैं; लेकिन इस अंतर को 364-दिवसीय राजकोषीय ढुंडियों से होने वाली अधिक प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया गया है; ये ढुंडियां सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए नए पत्र (इन्सट्रमेंट) हैं।

37. संशोधित अनुमानों में कुल प्राप्तियों की राशि 1,17,524 करोड़ रुपए हैं जबकि इसकी तुलना में बजट अनुमानों में यह राशि 1,13,693 करोड़ रुपए थी। बजट घाटे की अनुमानित राशि 7202 करोड़ रुपए है तथा वर्ष का राजकोषीय घाटा 36,722 करोड़ रुपए बैठता है। ये आंकड़े बजट अनुमानों में परिकल्पित आंकड़ों से कुछ ऊंचे हैं लेकिन फिर भी ये वृहत्—आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से सहन करने योग्य सीमाओं के भीतर हैं।

38. अब मैं वर्ष 1993-94 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

39. पिछले वर्ष हमारे सामने आने वाली संसाधन संबंधी बाधाओं के कारण विकास संबंधी कार्यक्रमों पर एक जबरदस्त अंकुश सा लग गया, जिसका हम वर्ष 1992-93 में वित्त-पोषण कर सकते थे। वर्ष 1992-93 (बजट अनुमान) में केन्द्रीय आयोजना की कुल राशि पिछले वर्ष में की गई व्यवस्था के मुकाबले केवल 12.6 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष

1992-93 के दौरान राजकोषीय स्थिति में सुधार होने तथा मुद्रास्फीति में कमी आने से अब हम राजकोषीय घाटे में निरंतर सुधार को सुनिश्चित करते हुए आयोजना को बढ़ावा देने की स्थिति में हैं। तदनुसार, वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 63,936 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो कि वर्ष 1992-93 के 84,407 करोड़ रुपए के आंकड़े की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।

40. केन्द्रीय आयोजना को 23,241 करोड़ रुपए तक की सीमा तक बजटीय सहायता से वित्तपोषित किया जाएगा जो कि वर्ष 1992-93 में प्रदान की गई 18,501 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है। केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का 40,695 करोड़ रुपए का शेष धनराशि की व्यवस्था आंतरिक और बजट-तर संसाधनों से की जाएगी जो कि वर्ष 1992-93 में 29,906 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 36 प्रतिशत बढ़ोतरी की द्योतक है। वर्ष 1993-94 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं हेतु मैं 18,010 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान कर रहा हूँ जबकि वर्ष 1992-93 में यह सहायता राशि 16,111 करोड़ रुपए थी। केन्द्र और राज्यों की आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सरकार के बजट में से दी जाने वाली कुल बजटीय सहायता, जो वर्ष 1992-93 में 34,612 करोड़ रुपए थी, में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि करके वर्ष 1993-94 के लिए इसे 41,251 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

41. आयोजना के लिए बजटीय सहायता में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने से सामाजिक क्षेत्रों और ग्रामीण विकास से संबंधित केन्द्रीय आयोजना कार्यक्रमों को भी काफी बढ़ावा मिला है, ये कार्यक्रम बजटीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के आगामी वर्ष के परिव्यय में 62 प्रतिशत की बहुत बड़ी वृद्धि करके इसे 5010 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा पूंजी निर्माण दोनों को ही अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। जवाहर रोजगार योजना के आबंटन की राशि बढ़ा कर 3306 करोड़ रुपए निर्धारित किया जा रहा है जब कि चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए आबंटित राशि 2046 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य रोजगार के 11,000 लाख श्रम-दिवस उत्पन्न करना है। यह प्रस्ताव है कि स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसम) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 लाख युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है और प्रावधान राशि को 1992-93 में 460 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 740 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए भी अधिक आबंटन राशियों की व्यवस्था की गई है। जैसा कि संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1991 में परिकल्पना की गई है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत

बमाने के फलस्वरूप विकेन्द्रीकृत योजनाओं और विनाश संबंधी कार्यक्रमों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा।

42. आठवीं योजना में मानव संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे हृदय के बहुत निकट है। इसलिए यह घोषणा करते हुए मुझे खासतौर पर खुशी महसूस हो रही है कि शिक्षा के लिए परिव्यय की राशि 952 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1310 करोड़ रुपये निर्धारित की जा रही है जो कि 37.6 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। संतोषजनक स्तर की प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता, विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं के लिए, की व्यापक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के आधुनिकीकरण के लिए पूर्वपेक्षा है। माननीय सदस्य को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूर्ण साक्षरता अभियान का विस्तार नए क्षेत्रों तक हो रहा है तथा अब इस योजना को 182 जिलों में कार्यान्वित करके लगभग 430 लाख प्रौढ़ विद्यार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही है। शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने तथा ऐसे जिलों, जहां पूर्ण साक्षरता अभियान सफल रहे हैं और जिनके फलस्वरूप वहां प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ गई, में एक नई स्कीम शुरू की जा रही है। प्रारम्भिक शिक्षा का व्यापीकरण करने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन जिलों में जिज्ञा-विशिष्ट तथा जन-संख्या-विशिष्ट योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े लगभग 200 जिलों, जहां पर महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत दर से कम है, में से बीस से लेकर पच्चीस जिलों को 1993-94 में जिज्ञा योजनाएं तैयार करने के लिए चुना जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और उन्नयन को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अकाशिकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नागालैंड में एक विश्वविद्यालय तथा असम में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया है।

43. स्वास्थ्य के लिए 483 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो चालू वर्ष के बजट में इसके लिए निर्धारित 302 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा संचरक और अन्य रोगों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए खर्च किया जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है; इस शीर्ष के अंतर्गत चालू वर्ष के 1000 करोड़ रुपये राशि के प्रावधान को बढ़ा कर आगामी वर्ष के लिए 1270 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से 3250 लाख अमरीकी डालर की लागत वाला एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर

भी कम करने के उद्देश्य से, सामाजिक-भुरखा-तन्त्र योजना के अंतर्गत जनसंख्या की दृष्टि से पिछड़े 90 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आधारभूत ढांचों में सुधार करने के प्रयोजन से सहायता प्रदान की जाएगी।

44. पिछले वर्ष स्थापित किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार कर रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए चालू वर्ष के 360 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में आगामी वर्ष के लिए 474 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे हमें उक्त योजना के आधारभूत ढांचे को सज्जत बनाने में मदद मिलेगी। कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटित राशि 530 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 630 करोड़ रुपये कर दी गई। इसमें से 73 करोड़ रुपये की राशि सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए खर्च की जाएगी। अनुसूचित जातियों से संबंधित संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तौर पर 247 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के कार्यों का और अधिक विस्तार किया जाएगा।

45. सरकार कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मानती है। कृषि मंत्रालय की आयोजनागत स्कीमों, जिनमें पशुपालन और डेरी कारोबार भी शामिल हैं, के लिए 1408 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान में 36 प्रतिशत की वृद्धि करके 1918 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि से संबंधित परिव्यय का अधिकांश भाग राज्य की आयोजनाओं में शामिल है।

46. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, दूरसंचार, रेलवे तथा परिवहन जैसे आधारभूत क्षेत्रों की आवश्यकताओं की भी अवहेलना नहीं की गई है। इन क्षेत्रों के निवेश संबंधी कार्यक्रमों को सरकारी उद्यमों अथवा विभागीय तौर पर चलाए जाने वाले वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है तथा इन संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आंतरिक और बजट-तर संसाधनों के द्वारा योजना परिव्यय के लिए धनराशि की व्यवस्था करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए आयोजना परिव्यय को चालू वर्ष के 6208 करोड़ रुपये की राशि से लगभग दोगुना करके 12,114 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। विद्युत क्षेत्र के चालू वर्ष के 5167 करोड़ रुपये के परिव्यय में 22 प्रतिशत वृद्धि करके इसके लिए 6269 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सड़कों के लिए प्रावधान की राशि 464 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 593 करोड़ रुपये निर्धारित कर दी गई है। रसायन और पेट्रो-रसायन के लिए भी परिव्यय राशि 763 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1206 करोड़ रुपये कर दी गई है। रेलवे के लिए आयोजना परिव्यय 5700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर

करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जिसमें कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

47. अब मैं आयोजना-भिन्न व्यय की चर्चा करूंगा। मैं सदन का ध्यान व्याज अदायगियों के भारी बोझ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बारे में, चालू वर्ष के 32,500 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में वर्ष 1993-94 के लिए 38,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। व्याज का यह भारी बोझ सरकारी ऋण की बढ़ती हुई मात्रा के कारण है जो स्वयं ही साल दर साल होने वाले बड़े राजकोषीय घाटों को दर्शाता है। तथापि, राजकोषीय घाट कम कमा हान आर इस प्रकार सरकारी ऋण कम भा कमा आने से यह आशा की जाती है कि 1995-96 तक इस मद में तेजी से गिरावट आएगी।

48. रक्षा संबंधी व्यय के लिए प्रावधान की राशि चालू वर्ष के 17,500 करोड़ रुपए से बढ़ा कर आगामी वर्ष के लिए 19,180 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। उर्वरकों तथा निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता राशियों की आवश्यकताएं काफी कम हो जाएंगी जो इन आर्थिक सहायता राशियों को तर्कसंगत बनाने के लिए पहले से ही किए गए उपायों के प्रभाव को दर्शाती हैं। फार्म ऋण छूट स्कीम पर 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा; तथा इसके साथ ही इस स्कीम के अंतर्गत अदायगी करने संबंधी सरकार के वचन की भी पूर्ति हो जाएगी। चालू वर्ष के 2800 करोड़ रुपए की तुलना में, आगामी वर्ष के लिए मैं खाद्य आर्थिक सहायता के तौर पर 3000 करोड़ रुपए राशि की व्यवस्था कर रहा हूँ। सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता का बोझ एक समुचित स्तर पर ही बना रहे तथा इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि समाज के कमजोर वर्गों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। 1993-94 के लिए अन्य आयोजना-भिन्न व्यय, जिसमें व्याज पर किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं है, के प्रावधान की राशि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 3180 करोड़ रुपए कम है। पिछले वर्षों की भांति, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, जो अगले वर्ष देय हो जाएगा, के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। सभी मंत्रालयों को अनुमोदित बजट प्रावधान में से ही इस अतिरिक्त खर्च को वहन करना होगा।

49. अब मैं प्राप्तियों का उल्लेख करूंगा। चालू वर्ष में 78,782 करोड़ रुपए की तुलना में कराधान के मौजूदा स्तर के अनुसार 89,389 करोड़ रुपए के सकल कर राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 20,525 करोड़ रुपए की तुलना में आगामी वर्ष के करो में राज्यों का हिस्सा 22,590 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चालू वर्ष के 3670 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में, बाजार उधारों के लिए मैं 3700 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ। वापसी अदायगियों की राशि घटाने के 520 GI/93—2.

बाद, विदेशी सहायता की राशि 6819 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि चालू वर्ष में यह राशि 5374 करोड़ रुपए थी। हालांकि, अगले वर्ष भारी संकट में जमा राशियों की परिपक्वता अवधि पूरी हो जाएगी फिर भी यह अनुमान है कि अगले वर्ष के दौरान लघु बचतों की निवृत्त संग्रहण राशि मौजूदा चालू वर्ष के 5500 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच जाएगी। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तरह, सरकारी उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियों के लिए 3500 करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था कर रहा हूँ। मौजूदा कराधान के स्तरों के अनुसार 1,30,990 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियों तथा 1,31,323 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है जो 333 करोड़ रुपए के अंतर को दर्शाता है।

भाग 'ख'

50. अब मैं वर्ष 1993-94 के लिए कर प्रस्तावों पर आता हूँ।

51. इन प्रस्तावों को तैयार करने में मैं एकतरफ कर-डॉंच में व्यापक सुधार की अपेक्षाओं और दूसरी तरफ आयोजना में हुई विशाल वृद्धि के वित्तपोषण के लिए राजस्वों को बचाने की आवश्यकता की परस्पर-विरोधी अपेक्षाओं के संबंध में अत्यन्त सचेत रहा हूँ। पिछले वर्ष वैयक्तिक आय कराधान में चैलेन्जर्स समिति की सिफारिशों पर आधारित महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। चैलेन्जर्स समिति की विस्तृत सिफारिशों के प्राप्त हो जाने तक निगमिता कराधान के सुधार को आस्थ-गित रखा गया था। अब ये सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं। समिति ने हाल ही में अग्रत्यक्ष करों पर भी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें सीमा-कर शूलकों में महत्वपूर्ण कमी करने के साथ-साथ उत्पाद-शूलकों के युक्तिकरण और उनके सरलीकरण के बारे में सिफारिश की गई है।

52. मैं चैलेन्जर्स समिति की प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष दोनों करों पर की गई सिफारिशों के मुख्य प्रतिबल को स्वीकार करता हूँ। हमें यथासंभव प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में तेजी से मध्यम कर दरों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए, जिससे बेहतर कर बसुली को प्रोत्साहन मिलेगा यदि इसे कर आधार को विस्तृत बनाने के प्रयासों से अनुपूरित किया जाए। हमें निम्न से मध्यम सीमा-शूलकों की व्यवस्था की ओर भी अवश्य जाना चाहिए, जो वक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगीकरण के लिए अनिवार्य है। उत्पाद-शूलकों की निम्न दरें रखकर हमें इन्हें सरलीकृत करना चाहिए और हमारा दीर्घवाधिक लक्ष्य मूल्य-वधित कर प्रणाली की ओर जाने का होना चाहिए। लेकिन, राष्ट्रव्यापी मूल्य-वधित कर प्रणाली रातों-रात शुरू नहीं की जा सकती। ऐसी प्रणाली की रूपरेखा के बारे में केन्द्र और राज्यों के बीच एक व्यापक सहमति करनी होगी। एक सुविज्ञ विचार-विमर्श और वाद-विवाद के

संवर्धन के लिए मैं राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्था से एक संभव मूल्य-वर्धित कर प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ।

52. यद्यपि चैलेय्या समिति की सभी प्रमुख सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं, परन्तु उन्हें इस साधारण कारण से तत्काल कार्यान्वित नहीं किया जा सकता कि ऐसा कर सुधार, जो विस्तृत आधार पर निम्न कर दरों के संग्रहण का समावेश करता हो प्रायः अल्पावधि में राजस्व में हानि करता है। राजकोपीय विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि राजस्व की हानि की पूर्ति अल्पावधि में की जाएगी, परन्तु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा तत्काल हो जाएगा और वित्त मंत्री यदि मध्यम-वर्धित में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अल्पावधि का ध्यान रखना होता है। मैं आशा करता हूँ कि सदन मेरे साथ इसमें सहमत होगा कि एक चरणबद्ध परिवर्तन की आवश्यकता है।

53. परिवर्तन को चरणबद्ध करने में एक मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सभी मोचों पर थोड़ा कार्य किया जाए या अग्रिम में अन्य क्षेत्रों में की जाने वाली प्रगति की स्पष्ट घोषणा के साथ कतिपय क्षेत्रों में निर्णायक परिवर्तन किए जाएं। मैंने इस विषय में ध्यानपूर्वक विचार किया है और मैं महसूस करता हूँ कि सभी मोचों पर मामूली सुधारों की तुलना में ताजुक क्षेत्रों में निर्णायक कार्रवाई करना अधिक महत्वपूर्ण है। मौजूदा तौर पर कार्रवाई के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमा-शुल्कों का है। पिछले दो बजटों में सीमा-शुल्कों में किए गए समायोजनों के बावजूद हमारे शुल्क, विशेष रूप से पूंजीगत सामग्री पर, हमारे अधिकांश प्रतिस्पर्धी देशों के शुल्कों से अभी भी बहुत ऊंचे हैं। इन शुल्कों और परिणामी उच्च पूंजीगत लागतों के रहते हुए हमारे उत्पादक कभी भी विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं होंगे। यदि उच्च सीमा-शुल्क उन्हें अस्पर्धात्मक बनाते हैं तो हम नए निवेश, घरेलू और विदेशी दोनों के निर्यात बाजार संबंधी क्षेत्रों की ओर प्रवृत्ति होने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर भी, यदि हम विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, तो मौजूदा तौर पर हमें ऐसे निवेशों की ही अत्यंत प्रेरणा है। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि हम प्रतिस्थापन की क्या कीमत चुकाते हैं, इस विश्वास से कि आयातों के प्रतिस्थापन से स्वतः ही आत्म-निर्भरता में योगदान मिलता है, एक मात्र स्वदेशी बाजार को लक्ष्य बनाकर उद्योग स्थापित न तो कर सकते हैं और न ही करने चाहिए। वस्तुतः यह केवल अदक्ष औद्योगिकरण को पोषित करता है जिसमें निर्यात करने की एक अयोग्यता और विदेशी सहन्यता पर स्थायी निर्भरता पैदा होती है। हमारे उद्योग की उचित सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखते हुए, हमें इस क्षेत्र में साहसिक पहल करनी चाहिए। सामान्यतः सीमा-शुल्क घटने से हुई राजस्व की हानि को उच्च उत्पाद-शुल्कों के माध्यम से पूरा किया जा सकता था। लेकिन, विस्तृत रेंज के उद्योगों में उत्पाद-शुल्कों के युक्तिकरण तथा उन्हें कम करने के लिए बाध्यकारी

कारण हैं क्योंकि हमारी बहुत सी शुष्क अत्यधिक ऊंची हैं और उद्योग के कुछ हिस्से मंदी की स्थितियों से ग्रस्त हैं।

55. इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य सहमत होंगे कि मेरे पास प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में फेर-बदल करने की सीमित गुंजाइश है। चैलेय्या समिति द्वारा सुझाए गए उपायों के अनुरूप निगमित कर ढाँचे में प्रमुख सुधार निस्संदेह वांछनीय है। परन्तु पूर्वोक्त कारणों से इसे अगले वर्ष तक आस्थगित रखा जाएगा।

56. फिर भी, मैं उन राज्यों में नए निवेश के लिए प्रोत्साहन देना चाहूंगा जिनमें सभी जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तदनुसार, उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा तथा अंदमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों के लिए मैं उत्पादन के वर्ष से शुरू करके पांच-वर्षीय करावकाश का प्रस्ताव करता हूँ।

57. हमारी अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण निविष्टि है। इसलिए मैं भारत में किसी भी स्थान पर विद्युत उत्पादन या उत्पादन एवं वितरण के लिए स्थापित किए गए नए औद्योगिक उपक्रमों के लाभों और प्राप्तिशतों के संबंध में पांच-वर्षीय करावकाश शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। पांच-वर्षीय करावकाश विद्युत के उत्पादन वर्ष से शुरू होगा।

58. इन दोनों मामलों में पांच-वर्षीय करावकाश आयकर अधिनियम की धारा 80 I क का हिस्सा होगा। पांच-वर्षीय अवधि के अंत में ये इकाइयां शेष अवधि के लिए धारा 80 I क के अंतर्गत मौजूदा कटौती की हकदार होंगी।

59. एक स्वच्छतर और अधिक स्वस्थ पर्यावरण के संवर्धन के लिए मैं पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण-नियंत्रण से संबंधित संयंत्र और मशीनरी पर आयकर नियमों के अधीन पूंजीगत लागत पर मौजूदा 40 प्रतिशत की अपेक्षा शतप्रतिशत ग्राह्य मूल्यहास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

60. अब तक, उच्च शिक्षा की हमारी संस्थाएं लगभग पूर्णतः सरकारी निधियों पर निर्भर रही हैं। चूंकि सरकारी निधियां सीमित हैं, इसलिए हमें उद्योग से इन संस्थाओं के लिए निधि उपलब्ध कराने के तरीकों का पता लगाना चाहिए। ऐसा करने से वे उद्योग के निकट लाई जा सकेंगी और वे इस प्रकार उद्योग की जरूरतों के लिए प्रतिसंवेदी बनेंगी। इसलिए मैं अनुमोदित विश्वविद्यालयों, औद्योगिकी संस्थानों और समतुल्य संस्थाओं को दिए जाने वाले अंशदानों पर आयकर कटौती की मौजूदा 50 प्रतिशत दर को बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

61. आधुनिक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ आधार एक अनिवार्य पूर्वपिका है। भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने यह बार-बार सिद्ध किया है कि यदि उन्हें काम करने का उचित वातावरण, उचित प्रेरणा और पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हों तो वे विश्व में किसी अन्य वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से कम नहीं हैं। भारतीय उद्योग को अनुसंधान और विकास पर और काफी अधिक खर्च करने की जरूरत है। ऐसा करने में मैं उद्योग को हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। इस उद्देश्य के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के संबंध में अनुसंधान में लगी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों के लिए धन और व्यवसायों की आय से दिए गए अंशदान पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। यह भारित कटौती केवल उन्हीं अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगी जो अनुसंधान के प्रयोक्ताओं और उसके उत्पादकों द्वारा निश्चित किए गए हों तथा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति किए गए हों।

62. मैं आयकर की धारा 10 क के अधीन वर्तमान में मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को उपलब्ध पाच-वर्षीय करावकाश, को साफ्ट वेयर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क) और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क) में स्थापित इकाइयों को भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। जुलाई 1991 में मैंने साफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त हुई आय के संबंध में तीन वर्ष के लिए शत-प्रतिशत कटौती लागू की थी। साफ्टवेयर का अच्छा निर्यात हुआ है तथा मैं और एक वर्ष के लिए अर्थात् निर्धारित वर्ष 1994-95 के लिए यह रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

63. हमारे पूंजी बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति देने की योजना के अधीन हमने यह इंगित किया था कि ऐसे निवेशकों को उनके निवेश से आय पर 20 प्रतिशत और दीर्घावधि पूंजी अभिलाभों पर 10 प्रतिशत कर लगेगा। मैं ऐसे निवेशकों के लिए अल्पावधि पूंजी अभिलाभों के संबंध में भी 30 प्रतिशत की रियायती दर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

64. जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, चैलेय्या समिति की सिफारिशों के आधार पर पिछले वर्ष वैयक्तिक कराधान में काफी सुधार किया गया था। मैं दर ढाँचे और छूट सीमा को अपरिवर्तित छोड़ने और केवल कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

65. पिछले वर्ष, संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण, मैं 1 लाख रुपये से ऊपर की वैयक्तिक आय पर अधिभार को 12 प्रतिशत पर ही रखने के लिए बाध्य

हुआ था। मैंने चालू वर्ष में अधिभार को हटाने के योग्य हो जाने की आशा की थी परन्तु मैं इसे और एक वर्ष तक जारी रखने के लिए बाध्य हूं। तथापि, मैं वेतन से होने वाली आय से मानक कटौती को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और 75,000 रुपये तक की आय वाली कामकाजी महिलाओं के लिए मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

66. मुद्रास्फीति के इन दिनों में वृद्ध लोगों की कठिनाई को समझते हुए मैंने पिछले वर्ष उन वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी सकल कुल आय 50,000 रुपये से कम थी, को 10 प्रतिशत की कर रियायत प्रदान की थी। मैं यह कर रियायत बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और आय सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये से 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

67. पिछले वर्ष मैंने यह घोषणा की थी। कि अनिवासियों से संबद्ध लेन-देनों के संबंध में अग्रिम निर्णय की एक योजना तैयार की जाएगी। यह योजना तैयार कर ली गई है और मैं एक सांविधिक प्राधिकरण के सृजन के लिए विधायी प्रस्ताव सामने ला रहा हूं। जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। मैं आशा करता हूं कि अनिवासियों द्वारा इस योजना का स्वागत किया जाएगा।

68. मैं पिछले वर्ष शुरू की गई अनुमानित कराधान की सरलीकृत योजना को परिवहन प्रचालन, एक वाहन को भाड़े पर देने अथवा पट्टे पर देने वाले छोटे सड़क परिवहन प्रचालकों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

69. सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन की गई अदायगियों को आयकर से पूरी तरह जो छूट प्राप्त हैं, पिछले वर्ष मैंने यह छूट निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उपलब्ध की थी। मैं अब यह सुविधा सांविधिक प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव करता हूं।

70. विकलांग शिशु का पालन-पोषण करने की मानविक परेशानी को समझते हुए मैंने पिछले वर्ष विकलांग अंगरंगों के अभिभावकों के लिए आयकर कानून के अंतर्गत अनुमेय कटौतियों को 6,000 रुपये से 12,000 रुपये तक बढ़ाया था। मैं अब इस कटौती को आगे 15,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं विकलांग अवयस्कों की उनके माता-पिता की आय से जोड़ी गई आय के संबंध में कटौती की शिशु के अधिकतम 20,000 रुपये की आय की पूर्ण सीमा तक अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

71. जुलाई, 1991 में अपने पहले बजट भाषण में, मैंने साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था। यह प्रतिष्ठान गृह मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित हो चुका है। मैं अब इस प्रतिष्ठान को किए जाने वाले दान के संबंध में आयकर

अधिनियम की धारा 30B के अधीन शीत-प्रतिशत की कटौती की लागू देने का प्रस्ताव करता है। मैं राष्ट्रीय साम्प्रदायिक संबंधों प्रतिष्ठान की आय की आयकर से पूरी तरह छूट देने की भी प्रस्ताव करता हूँ।

72. वर्तमान में, धर्मार्थ स्थाओं और संस्थाओं की प्रत्येक तीन वर्ष में आयकर अनुदान का अनुमोदन प्राप्त करना होता है, ताकि उन्हें दिए गए प्राप्त छूट के लिए पात्र हो जाए। कांजी कारंदाई को कम करने और कार्यालय की सरलीकृत करने के लिए, मैं आयकर द्वारा अनुमोदन की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर पाँच निर्धारण वर्ष तक करने का प्रस्ताव करता हूँ।

73. न केवल विश्व अर्थव्यवस्था में बल्कि खेल जगत में भी, मैं भारत को विशिष्टता प्राप्त देना चाहूँगा। आयकर अधिनियम में स्वीकृत खेल संघों अथवा संस्थाओं की आय के संबंध में छूट की अनुमति देने और उन्हें दिए जाने वाले दानों के संबंध में 5A प्रतिशत कटौती प्रदान करने की व्यवस्था है। ऐसे क्रियाकलापों में खेलकूद के संबंध को शामिल करने के लिए मैं अधिनियम की धारा 35-कग के अधीन प्राप्त परि-योजनाओं अथवा योजनाओं के संबंध में नियमों की संशोधित करने की प्रस्ताव करता हूँ। इससे अनुमोदित खेलकूद परियोजनाओं और योजनाओं पर व्यय करने के संबंध में शीत-प्रतिशत की कटौती प्रदान की जाएगी।

74. पिछले वर्ष, मैंने प्रत्यक्ष कर के मामलों में मुकदमों-बांजी के तत्काल निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव की निरस्त रूप से जाँच की गई है और मैं इस संबंध में ग्रीष्म ही एक विधान बनाने की आशा रखता हूँ। प्रत्यक्ष कर संहिता के संबंध में, संसद इस विषय पर चर्चा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेगी।

75. धन-कर अधिनियम की पिछले वर्ष काफी नया रूप दिया गया था और कराधान के आधार की धन से हटकर अनुसूचित परिवारों पर कर दिया गया था। यह दृढ़ संभव है कि एक शिक्षा नीति सांख्यिकी आवश्यकता है और इसे धन-कर के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। इसलिए मैं एक रिहायशी निवास के मूल्य अथवा उसके भाग को धन-कर लगाए जाने से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

76. पिछले वर्ष मैंने बिजली के माल (स्टॉक-इन-ट्रेड) के रूप में धारित रिहायशी ओवांसी, मोटर कारों आदि पर धन-कर लगाने से छूट दी थी। अब मैं बिजली के माल के रूप में धारित शहरी भूमि को छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन, स्टॉक, कारिता की आड़ में सट्टेबाजी की निरस्तता करने के लिए मैं उस वर्ष, जिसमें भूमि अधिग्रहीत की जाती है, से ब्रांज करके छूट को तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

77. दान-कर के उद्देश्य के लिए छूट की सीमा कुछ वर्ष पहले 20,000 रुपए नियत की गई थी। मैं कर-सुधार

समिति की सिफारिशों से सहमत हूँ कि इस सीमा को संशोधित करने की आवश्यकता है और इसलिए इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

78. किसी अभिमत रिश्तेदार को उसके विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों पर केवल 10,000 रुपए की सीमा तक दान-कर से छूट दी जाती है। जबकि तत्काल-भुक्त वाले विवाहों पर होने वाला विशाल व्यय कर से बच निकलता है। अतः और लाभकारी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं किसी अभिमत रिश्तेदार के विवाह के समय प्रदान की जाने वाली कर-छूट की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

89. निर्यात अभियान, जिसे हर कीमत पर बनाए रखा जाना है, को प्रोत्साहन देने के रूप में मैं बैंकिंग कंपनियों को उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले निर्यात संबंधी ऋण पर ब्याज-कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

80. मेरे द्वारा इन प्रस्तावित विभिन्न परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 300 करोड़ रुपए की हानि होगी, जिसमें राज्यों का हिस्सा 194 करोड़ रुपया होगा। यह राशि प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रहों के 2 प्रतिशत से भी कम, यानि बहुत छोटा आन है। मैं इसे बर ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आशा है कि करों के बेहतर संग्रह से इस हानि की पूर्ति हो जाएगी।

81. मैं अब अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आता हूँ।

82. वर्ष 1973 से हमें बुनियादी सीमा-शुल्क के अतिरिक्त एक शुल्क सहायक शुल्क संग्रहीत रहे हैं। शुल्क ढाँचे और निर्धारण प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए मैं शुल्क सहायक शुल्क को समाप्त करने और उसके बुनियादी शुल्क के साथ विलयन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

83. सीमा-शुल्क की पुनःसंरचना करने में हमारी पहली प्राथमिकता पूर्वाभित वस्तुओं और परिवोजना आवश्यकता के क्षेत्र में होती चाहिए क्योंकि ये शुल्क मूल निवासों के लिए प्रस्तावों पर प्रभाव डालते हैं। पिछले वर्ष परिवोजना और सामान्य मशीनरी पर शुल्क की 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया था। यह प्रतिस्पर्धी देशों में दूरों की तुलना में अधी की काफी ऊँची है और इसे और घटाना आवश्यक है। इसलिए मैं परिवोजना और सामान्य मशीनरी पर घटाने शुल्क कम करके इसे 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्युत, कोयला खनन और पेट्रोलियम-भोधन जैसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में औद्योगिक 30 प्रतिशत की शुल्क दर है। मैं कोयला खनन और पेट्रोलियम-भोधन के मामलों में इस दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्युत क्षेत्र के विशेष महत्व को देखते हुए, विद्युत परियोजनाओं पर शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है और यही दर विद्युत संयंत्रों के अधिनिकीकरण और नवीकरणीय के लिए आवश्यक मशीनरी पर भी लागू की जा रही है।

84. सदन को यह आश्चस्त करना चाहता हूँ कि पूंजीगत सामग्रियों पर शुल्कों को पुनःसंरचित करने में मैंने स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग के उचित हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया है। विभिन्न मंत्रालयों तथा संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में हमारा विस्तृत विचार-विमर्श हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित मशीनरी पर निम्न शुल्क दरों के कारण स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को हानि न पहुंचे, अवयवों पर आयात शुल्क को कम करना आवश्यक है ताकि हमारे विनिर्माता प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बन सकें। इसलिए मैं सामान्य मशीनरी के अवयवों पर शुल्क को वर्तमान 40 प्रतिशत अथवा 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे अवयवों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, मैं "मोडवाट" के अधीन क्षतिपूर्ति की पूर्ण सुविधा के साथ 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिस्तुलनकारी शुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

85. मौजूदा तौर पर विभिन्न किस्मों के मशीनों औजार सहित अन्य कई पूंजीगत वस्तुएं हैं, जिन पर 60 प्रतिशत से 110 प्रतिशत के बीच में शुल्क की विभिन्न दरें लगती हैं, ऐसे उपकरण भी हैं, जिनपर 40 प्रतिशत से लेकर 110 प्रतिशत तक शुल्क लगता है। मैं इस ढांचे का तीन शुल्क दर खण्डों (स्लोड्स) अर्थात् 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत में युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस युक्तिकरण में सामान्यतः 20 से 30 प्रतिशतांक के बीच शुल्क में कमी होना शामिल है। फलस्वरूप, निविष्ट पुर्जों और अवयवों पर शुल्क की दरों में कमी की जा रही है।

86. हस्त-चालित औजार शिल्पकारों और कुशल कामगारों के लिए पूंजीगत सामग्रियां होती हैं और इन पर मौजूदा तौर पर 40 प्रतिशत से लेकर 110 प्रतिशत तक का शुल्क लगता है। मैं इन सभी औजारों के लिए 40 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

87. पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क कम करने का तर्क धातु और साथ ही धातु सामग्रियों पर शुल्क कम करने की अपेक्षा करता है, क्योंकि ये स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग की बुनियादी कच्ची सामग्रियां हैं। तदनुसार, स्वदेशी उत्पादकों की सहायता करने के लिए मैं अधिकांश मामलों में लौह धातुओं पर शुल्क दरों में 10 से 20 प्रतिशतांक तक की कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन परिवर्तनों के अनुरूप, इस्पात कतरन (स्क्रैप) पर आयात शुल्क का 15 प्रतिशत पर पुनर्निर्धारण किया जा रहा है; निविष्ट उष्म-सह (रिफ़ैक्ट्री) संबंधी कच्चे माल पर आयात शुल्क कम करके 30 प्रतिशत किया जा रहा है। अब मैं अलौह धातुओं पर आता हूँ तथा इनमें से अधिकांश मदों पर शुल्क दरों में 10 से 55 प्रतिशतांक तक की कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। अनगढ़ और अमिश्रधातुओं पर शुल्क की परि-

णामी दरें 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच तथा गढ़ी हुए धातुओं पर 70 से 80 प्रतिशत तक के बीच रहेगी।

88. रसायनों का शुल्क ढांचा दरों, की बहुलता और कई असंगतियों द्वारा परिलक्षित होता है। निविष्टियों पर शुल्क प्रायः तैयार उत्पादों पर शुल्कों के अनुरूप नहीं होते हैं। इसलिए मैं ऊपरी सिरे पर शुल्क दरों को काफी कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि निविष्टियों पर शुल्क दरें सामान्यः अतिम उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक नहीं हों, रसायन पर शुल्क दरों को पुनः संरचित करने का करने का प्रस्ताव करता हूँ। एथिलीन, प्रोपिलीन बूटाडाईन, बेंजीन, स्टिरीन और एथिलीन डाई-क्लोराईड जैसे बुनियादी संभरक सामग्रियों (फीड-स्टॉक पर मौजूदा शुल्क दरें 25 और 80 प्रतिशत के बीच हैं। इन दरों को 15 प्रतिशत की एक समान निम्न शुल्क दर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। आईलीन्स, पैराजा-ईलीन्स, टोलूईन, एक्रीलोनार्डाईल और क्यूमीन पर शुल्कों को कम करके 40 प्रतिशत किया जा रहा है। डी. एम. टी. पी. टी. ए. और एम. ई. जी. इन पर उत्पादन की ऊंची कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुल्कों को कम करके इन्हें 70 प्रतिशत पर एक किया जा रहा है। तथापि, स्वदेशी इकाईयों के हित की पर्याप्त सुरक्षा करने के लिए केप्रोलेक्टम के मामले में शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है।

89. इलेक्ट्रानिक उद्योग हमारे निर्यात प्रयास में और रोजगार सृजन में एक भूमिका निभाता है, इसमें एक विश्व स्तरीय उद्योग बनने की क्षमता है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूँ। परियोजना आयातों और इलेक्ट्रानिक्स के लिए निविष्ट पूंजीगत सामग्रियों पर मौजूदा तौर पर शुल्क की दरें या तो 30 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत हैं, मैं इन दरों को 25 प्रतिशत की एक समान दर तक कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। कच्चे माल, छोटे-छोटे पुर्जों और अवयवों पर मौजूदा आयात शुल्क क्रमशः 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत लगाया जाता है। इन दरों को घटाकर क्रमशः 20 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 50 प्रतिशत किया जा रहा है। दूरसंचार क्षेत्र को विस्तृत और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। अतः आष्टिकल फाइबर केबल के निर्माण के लिए निविष्ट कच्चे माल पर आयात शुल्क में भारी कमी करके इसे 90 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

90. वस्त्र, चमड़ा, समुद्रीय उत्पाद, हीरे तथा जवाहरात आदि जैसे मौजूदा निर्यात-प्रमुख क्षेत्रों में हमें अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हैं, इनमें अपनी निर्यात क्षमता को मजबूत करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों से संबंधित निविष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर मैं आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके

अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी तथा पुष्पोत्पादन उद्योगों जैसे कुछ क्षेत्रों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निर्यात मदों पर परम ध्यान केन्द्रित करने संबंधी श्रुतियों (ग्रुप्स आन एक्सट्रीम फोकस आयटम्स फार एक्सपोर्ट) ने कुछ सिकारियों की हैं। तदनुसार, इन क्षेत्रों के लिए निविष्टियों पर आयात शुल्क घटा कर 25 प्रतिशत किया जा रहा है।

91. समुद्री जहाज को तोड़ने से संबंधित उद्योग रोज-वार-प्रधान है तथा यह हमारे इस्पात उद्योग के गौणक्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं इससे संबंधित आयातों पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत का निम्न सम्प्रविष्ट सीमा-शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे समुद्री जहाजों को तोड़ने से प्राप्त होने वाली लौह सामग्री पर मौजूदा तौर पर जो उत्पाद शुल्क लगता है, उसे बिलकुल समाप्त किया जा रहा है।

92. लम्बाई की दृष्टि से हमारा फिल्म उद्योग विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। हालांकि, इस उद्योग ने प्रोत्साहनों की किसी खास जरूरत के बिना ही यह दर्जा प्राप्त कर लिया है, लेकिन इस उद्योग को अब इलेक्ट्रॉनिकी तंत्र से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है और इसलिए इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का औचित्य है। इसलिए, मैं सिने पोजिटिव फिल्मों के जम्बों रोल पर शुल्क 55 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत तथा तैयार सिने फिल्म रोल पर लगभग 65 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं नेगेटिव सिने फिल्मों पर भी शुल्क की दर 35 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

93. ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों, विशेषकर सौर, ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्योग के निविष्ट कच्चे माल तथा मदों पर उत्पाद-शुल्क की दर में 15 से 25 प्रतिशत तक की कमी की जा रही है। पवन चालित बिजली जेनरेटरों पर आयात शुल्क को भी 40 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

94. बंगलादेश के प्रति सौहार्द के प्रतीक के रूप में, मैं प्रसिद्ध जामदानी साड़ियों को आयात शुल्क अदायगी से पूर्णतया मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। स्वदेशी क्षेत्र में निकासी के लिए लघु क्षेत्र की इकाइयाँ जहाँ उत्पाद-शुल्क से उन्मुक्त हैं, वही उन्हें नेपाल और भूटान को निर्यात की गई वस्तुओं पर इस समक उत्पाद शुल्क अदा करना पड़ता है। मैं इन इकाइयों को इस शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि बसेस (सार्क) देशों के साथ व्यापार और बेहतर करने में हम कदमों का योगदान होगा।

95. मौजूदा तौर पर, मान्यता-प्राप्त प्रेस कैमरामैन 60,000 रुपये तक के मूल्य के फोटोग्राफी उपकरणों का सीमा-शुल्क-मुक्त आयात कर सकते हैं। लेकिन अन्य पत्रकारों को

ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वे लैपटॉप कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, फैक्स मशीन तथा टाइपराइटर आदि जैसे विशिष्ट उपकरण का आयात कर सकें। कहीं क्या इसी वजह से तो समाचारपत्रों में छपे मेरे (फोटो) संपादकीय टिप्पणियों से बेहतर होते हैं—मैं अक्सर सोचता हूँ। भारतीय पत्रकारिता में आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के मेरे निश्चय के फलस्वरूप तथा देश में आर्थिक सुधार-संबंधी प्रश्नों की समझ को व्यापक बनाने में पत्रकारों ने जो ठोस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको दृष्टि में रखते हुए मैं मान्यता-प्राप्त पत्रकारों को भी 60,000 रुपये तक के मूल्य तक ऐसे उपकरणों के शुल्क-मुक्त आयात की सुविधा देने का प्रस्ताव करता हूँ; यह सुविधा केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।

96. यात्री सामान की कुछ निविष्ट मदों पर शुल्क को हाल ही में 255 प्रतिशत से घटा कर 150 प्रतिशत किया गया था। इस प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से मैं आम सामान पर शुल्क की दर को भी 255 प्रतिशत से घटा कर 150 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

97. अलग-अलग क्षेत्रों के लिए आयात शुल्कों में की गई कमियों के अनुरूप तथा मौजूदा विनियम दरों को ध्यान में रखते हुए सभी मदों पर शुल्क की अधिकतम दर को कम कर दिए जाने की गुंजाइश है। तदनुसार मैं यात्री सामान और मद्यसारिका (एल्कोहलिक) पेयों सहित कुछ मदों को छोड़कर शुल्क की अधिकतम दर 110 प्रतिशत से घटा कर 85 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

98. मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्यों को यह चिंता होगी कि आयात-शुल्कों को घटाने और आयात को उदार बनाने से हमारे उद्योग पर कहीं अत्यधिक दबाव न पड़े तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा और तैयार माल की डम्पिंग से वह कमजोर न हो जाए। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है तथा इन प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्योग पर कोई अनुचित दबाव नहीं पड़ेगा। पिछले दो वर्षों के दौरान विनियम दर में किए गए परिवर्तनों से, शुल्क में, स्वदेशी उद्योग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कमी करने की काफी गुंजाइश पैदा हो गई है। इसके अलावा मैं कच्चे माल और निविष्टियों पर से भी शुल्क दर में कटौती कर रहा हूँ जिससे हमारे उत्पादकों की उत्पादन लागत में कमी आने से वे अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनेंगे। इन परिवर्तनों के बावजूद भी तैयारमुदा उत्पादों पर शुल्क चलेय्या समिति द्वारा अनुशंसित दीर्घावधिक संरचना से काफी ऊंचे होंगे। हम उस लक्ष्य की ओर चरणों में अगले कुछ वर्षों में जा सकते हैं। जहां तक सामान एकत्र करके (डम्पिंग से) अनुचित प्रतिस्पर्धा होने का प्रश्न है, इस बारे में हमारे एकत्रीकरण-रोधी कानून पहले से ही लागू हैं तथा जब भी आवश्यकता होगी इन कानूनों के अंतर्गत तेजी से कार्रवाई की जाएगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही एक मामले में सामयिक कार्रवाई की गई है।

99. पिछले वर्ष के बजट में लौह अयस्क और बिना पालिश के ग्रेनाईट पर निर्यात शुल्क लगाए गए थे। इन क्षेत्रों द्वारा महसूस की जा रही कुछ कठिनाइयाँ मेरी जानकारी में लाई गई हैं। इसलिए मैं लौह अयस्क तथा बिना पालिश के ग्रेनाईट पर से निर्यात शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

100. अब मैं उत्पाद शुल्क से संबंधित अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूँगा। कर्षकों को सरल बनाने, ग्राम लोगों के उपभोग की वस्तुओं के संबंध में कुछ राहत देने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और पूँजीगत लागतों में कमी करने की दृष्टि से स्वदेशी पूँजीगत वस्तु उद्योग की सहायता करने के लिए, मांग की कमी से प्रभावित उद्योगों की सहायता करने तथा लघु उद्योगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्यों से ये प्रस्ताव से अनुप्राणित हैं।

101. 1988 से विशेष उत्पाद शुल्क के रूप में एक अधिभार लगाया गया जिसकी मौजूदा दर मूल उत्पाद शुल्क का 15 प्रतिशत है। इस प्रक्रिया के सरलीकरण की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि परिणामी शुल्क दरों का युक्तिकरण करते हुए मूल उत्पाद शुल्क के साथ विशेष उत्पाद शुल्क अधिभार का विलयन कर दिया जाए।

102. मुद्रा स्फीति से बुरी तरह प्रभावित हुए ग्राम लोगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मैं ग्राम लोगों के उपभोग की बहुसंख्यक वस्तुओं पर कराधान में कुछ राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ। काफी, चाय, इंस्टेंट चाय को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मैं वनस्पति पर से भी उत्पाद शुल्क की दर 1,900 रुपये से कम करके 1,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के अंतर्गत चल रही इकाइयों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नकद राशि की सहायता से चलाई जा रही इकाइयों द्वारा निर्मित जूतों को, मूल्य सीमा का लिहाज किए बिना, उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अन्य इकाइयों द्वारा निर्मित जूतों के संबंध में मैं रियायत के प्रयोजन से वर्तमान मूल्य सीमा को 75 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति जोड़ा करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं निम्नलिखित उत्पाद शुल्कों में भी कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ :—

- वाष्पणिक कूलरों पर 23 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;
- बिजली के पंखों पर 17.25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;
- निदिष्ट घरेलू बिजली के उपकरणों पर 23 प्रतिशत से 15 प्रतिशत;
- ड्राई सैल बैटरियों पर 34.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत;
- मुद्रण और लेखन स्याही पर 17.25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;
- रेडियो सेट पर 23 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;
- दंत भंजन पाउडर पर 17.25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

— नुडल और घुने हुए खाद्यान्नों पर 17.25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

— बिस्किट पर 11.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत;

— सांचे में ढलाई करके प्लास्टिक से निर्मित सामान पर 34.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत;

— कोशिकामय खंभे से बने गद्दे और बिस्तर जैसी मदों पर 69 प्रतिशत से 30 प्रतिशत।

103. मौजूदा तौर पर पूँजीगत वस्तुओं और यंत्रों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दरें 11.5 प्रतिशत से लेकर 23 प्रतिशत तक हैं। पूँजी लागत को कम करने और निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं बड़ी संख्या में पूँजीगत वस्तुओं और यंत्रों की मदों पर उत्पाद-शुल्क को कम करके इसे 10 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्युत क्षेत्र के लिए मैं इस दर को और भी घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

104. औद्योगिक विकास का पुनर्स्थापन हमारी वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित कार्यनीति का प्रमुख तत्व है। ऑटोमोटिव क्षेत्र, टेलीविजन और रेफ्रिजिरेशन तथा एयर कंडीशनिंग उद्योग मौजूदा तौर पर मंदी से ग्रस्त हैं। इन उद्योगों में लगे कामगारों का भविष्य अनिश्चित है। यदि मंदी की मौजूदा प्रवृत्ति को न उल्टा गया तो राजस्व की संभावनाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उत्पाद-शुल्कों में कमी करके इन उद्योगों को मैं पर्याप्त राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि इस प्रोत्साहन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेगी।

105. सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं साभान और यात्रियों को लाने ले जाने के लिए पेट्रोल के बिना चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद-शुल्क 23 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके साथ ही, ऐसे वाहनों के चैसिस पर भी उत्पाद-शुल्क घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं बसों तथा इसी प्रकार के यात्री-वाहनों के चैसिस पर ढांचे के निर्माण पर से उत्पाद-शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर देने का प्रस्ताव भी करता हूँ। तिपहियों (थ्री-व्हीलर) पर से उत्पाद-शुल्क की दर 23 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत की जा रही है। मैं मोटर कारों पर उत्पाद-शुल्क 55 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

106. रंगीन टेलीविजन पर विशिष्ट उत्पाद-शुल्क की दर, जो इस समय 1,925 रुपये से 4,785 रुपये प्रति सैट के बीच है, को घटा कर 1,250 रुपये से 2,200 रुपये प्रति सैट निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

107. मौजूदा तौर पर रेफ्रिजरेटरों पर उनकी क्षमता के अनुसार 575 रुपये से 5,750 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर तक का उत्पाद-शुल्क लगता है। मैं इन दरों को घटा कर 400

रुपए से 3,800 रुपए प्रति रेफीजरेटर तक करने का प्रस्ताव करता है। अन्य रेफीजरेटिंग उपकरणों, जिसमें कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी शामिल हैं, पर इस समय 69 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगता है। यह शुल्क अत्यधिक ऊँचा है तथा इससे खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रतिरक्षण उद्योगों की संवृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, मैं शुल्क को घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। एयर-कंडीशनर पर उसकी क्षमता के अनुसार प्रति तन 13,800 रुपए से लेकर 85,100 रुपए तक लगने वाले सीजुदा उत्पाद-शुल्क को घटा करके मैं इसे प्रति तन 7,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव करता हूँ। 7.5 टन तक की क्षमता वाले एयर कंडीशनर के कम्प्रेसरों पर उत्पाद-शुल्क 8,900 रुपए से घटा कर 5,500 रुपए प्रति कम्प्रेसर करने का प्रस्ताव करता हूँ।

108. निम्न और उच्च घनत्व वाले पोलिथीलीन, पोलिबिनाइल क्लोराइड, पोलिस्टीरीन आदि जैसी थोक प्लास्टिक रेशियों पर से उत्पाद-शुल्क की 46 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उद्योग से प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करने वाली छोटी इकाइयों को लाभ पहुंचेगा।

109. धातु, उद्योगों के बुनियादी कच्चे माल होते हैं तथा कर सुधार समिति ने, इस श्रेणी पर उत्पाद शुल्क में कमी करने का सुझाव दिया है। इसलिए मैं धातुओं को सीजुदा शुल्क संरचना के युक्तिकरण का प्रस्ताव करता हूँ। लौह धातुओं पर मूल्यानुसार शुल्क की दरें 11.5 प्रतिशत से लेकर 23 प्रतिशत के बीच होती हैं। मैं इन दरों को 12.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के दो स्तरों के रूप में युक्ति-संगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। एल्यूमीनियम पर लगने वाली शुल्क दरें 23 प्रतिशत से लेकर 40.25 प्रतिशत तक हैं। मैं इनके स्थान पर 25 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। तांबा, जस्ता, सीसा जैसी अन्य धातुओं पर 11.5 प्रतिशत से लेकर 34.5 प्रतिशत तक की शुल्क दरें लगती हैं। मैं इन पर शुल्क की 15 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुछ लौह धातुओं पर अभी भी विभिन्न दरों के अनुसार शुल्क लगता है। पिछले वर्ष से हुई मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैंने इन दरों में कुछ ऊर्ध्वगामी संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है।

110. परिवहन सुरक्षा के एक उपाय के रूप में और लकड़ी बनाने की दृष्टि से मैं प्लाईवुड पर उत्पाद शुल्क 34.5 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। लेखन और मुद्रण कागज के उत्पादन के लिए पावल और गेहूं की भूसी से बनी लुगदी तथा खोई, पटसन आदि से बनी हुई लुगदी की कम से कम 75 प्रतिशत मात्रा बलि अर्लेपित फ़ाट कागज को भी मैं उत्पाद शुल्क से पूर्ण मुक्ति की स्कीम में शामिल करता हूँ। इससे कर्माज के

निर्माण में और-आरम्भिक कच्चे माल के प्रयोग करने की गुंजाइश बढ़ेगी।

111. माचिस-उद्योग के यंत्रीकृत, अर्ध-यंत्रीकृत तथा गैर-यंत्रीकृत और कुटीर क्षेत्रों में इस समय क्रमशः 3.15 रुपये, 2.10 रुपये, 1.75 रुपये तथा 0.75 रुपया प्रति सौ माचिस की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने इस उद्योग द्वारा महसूस की जा रही कुछ कठिनाइयों तथा इसके ढाँचे में विद्यमान कतिपय असंतुतियों के बारे में मुझे अवगत कराया है। उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए मैं शुल्क की दर को घटा कर क्रमशः 2.40 रुपये, 1.25 रुपये, 1 रुपया तथा 0.50 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ तथा कुटीर क्षेत्र की मौजूदा रियायतें केवल उन्हीं इकाइयों तक सीमित रखने का भी प्रस्ताव है जो पंजीकृत सहकारी समितियाँ हो अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्राप्ति प्राप्त हो।

112. क्रान्तिवर्धक सामान और दैनिक प्रसाधन सामग्रियों जैसे टैलकम पाउडर, शीम्पू, चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीम, शोविंग क्रीम आदि पर 120.75 प्रतिशत की मौजूदा उत्पाद शुल्क दर अत्यन्त ऊँची है। समाज के एक विस्तृत वर्ग के लोगों द्वारा अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए इन सामग्रियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। मुझे इन सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क में कमी करने के संबंध में व्यापारियों, उपभोक्ताओं तथा महिला संगठनों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही नकदो प्रसाधन सामग्रियों और इस बहुत उच्च शुल्क की चोरी से संबंधित अन्य दुरुपयोग के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसलिए मैं क्रान्तिवर्धक सामान और प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद-शुल्क 120.75 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

113. मैं टायरों, ट्यूबा और फुलपा पर लगाए गए उत्पाद शुल्कों की निविष्ट दरों में मामूली ऊर्ध्वगामी संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

114. मैं शीरे पर उत्पाद-शुल्क की निविष्ट दरों में भी ऊर्ध्वगामी संशोधन करके उसे 172.50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

115. लघु क्षेत्र भारतीय उद्योग की शक्ति को और तथा नई उद्यमिता की नसरी रहा है। इस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क छूट योजना के केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अन्य उपायों के साथ-साथ इसके विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। मैं इस योजना के सरलीकरण और लघु इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए इसकी पुनः संरचना करने तथा इसके साथ ही प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की कतिपय सिफारिशों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता हूँ।

116. मैं पंजीकरण से छूट के लिए वर्तमान सीमा को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे अनेक छोटी इकाइयों को पंजीकरण की अनिवार्यता से मुक्ति मिल सकेगी और इसके साथ ही कर प्राधिकारियों के लिए अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयों पर अधिक ध्यान देना संभव होगा। मौजूदा तौर पर उत्पाद-शुल्क के एक अध्याय के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों के संबंध में पहले 20 लाख रुपए तक के उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट है और यह सीमा 30 लाख रुपए है, यदि उत्पादित वस्तुएं शुल्क के एकाधिक अध्याय के अंतर्गत आती हैं। मैं सभी इकाइयों के लिए शुल्क-सीमा छूट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे लघु क्षेत्र के निचले खण्ड में अनेक इकाइयों को लाभ पहुंचाना चाहिए।

117. मैं सोचता हूँ कि पुनर्संरचना के ही संदर्भ में, इस क्षेत्र की बड़ी इकाइयाँ राजकोष में कुछ अधिक योगदान कर सकती हैं। मौजूदा तौर पर शून्य शुल्क सीमा से ऊपर और 75 लाख रुपए तक के लिए देय उत्पाद-शुल्क सामान्य शुल्क घटा 10 प्रतिशत और कम से कम 5 प्रतिशत मूल्यानुसार है। मैं एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए तक के अनुमोदनों के लिए इसे बरकरार रखने का प्रस्ताव करता हूँ। 50 लाख रुपए से अधिक और 75 लाख रुपए तक के अनुमोदनों के लिए रियायती दर सामान्य शुल्क घटा 5 प्रतिशत और कम से कम 5 प्रतिशत मूल्यानुसार होगी।

118. लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं से वस्तुओं के खरीददारों को मौजूदा तौर पर मोडबॉट के अंतर्गत सांकेतिक ऋण मिलता है जो पूर्ववर्ती द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से 5 प्रतिशत अधिक होता है। लोक लेखा समिति ने इस सुविधा के संचालन में कुछ अनियमितताएँ पाई हैं। कर सुधार समिति भी इस विशेष छूट के जारी रखने के पक्ष में नहीं है जो अनिवार्यतः बड़े स्तर के प्रयोक्ता उद्योग की सहायता करती है। इसलिए, मैं इस उच्चतर सांकेतिक ऋण को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ जो लघु इकाइयों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के खरीददारों को मौजूदा तौर पर मिल रहा है। उन्हें मोडबॉट ऋण वास्तव में केवल भुगतान किए गए शुल्क के आधार पर ही मिलेगा।

119. कान्तिवर्धक प्रसाधनों और रेफ्रिजरेटर्स तथा वातानुकूलन उपकरणों के संबंध में, पिछले वर्षों में मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं लघु क्षेत्र के लिए उत्पाद-शुल्क छूटों को उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अनुमोदनों की मौजूदा पूर्ण छूट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। उसके बाद एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए तक के अनुमोदनों पर 50 प्रतिशत सामान्य शुल्क लगेगा। एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए से ऊपर के अनुमोदनों पर सामान्य शुल्क लगेगा। छूट की उदासीकृत योजना केवल उन्हीं इकाइयों को उपलब्ध होगी

जिनके अनुमोदनों का मूल्य एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं बैठता हो।

120. लघु क्षेत्र में सभी प्रस्तावित परिवर्तन पहली अप्रैल, 1993 से प्रभावी होंगे।

121. अब मैं कृषि, वस्त्रोद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों सहित कुछ प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

122. कृषि हमारे आर्थिक विकास के लिए प्रमुख है और यह विशेष राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाने का हकदार है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण और विविधीकरण करना है। मैं कृषि, बागवानी, वाणिज्य, मुर्गी-पालन आदि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी की विभिन्न मदों पर आयात शुल्क को 55 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं चावल के ट्रांसप्लान्टर्स पर आयात-शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं ग्रांड-पेरेंट मुर्गीपालन स्टॉक पर आयात-शुल्क को 105 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुछ एमिनो अम्लों पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

123. मछली पकड़ने में उपयोग की जाने वाली बाहरी बोर्ड युक्त (आऊट-बोर्ड) मोटरों के संबंध में मैं आयात-शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

124. मैं निर्दिष्ट कीटनाशकों पर आयात-शुल्क को 110 प्रतिशत से कम करके 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुछ कीटनाशक मध्यवर्तियों पर आयात-शुल्क दें, जो 65 प्रतिशत से 110 प्रतिशत के बीच हैं, उन्हें कम करके 50 प्रतिशत किया जा रहा है।

125. मैं बागवानी और पादप गृहों (ग्रीन हाउस) के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

126. मौजूदा तौर पर 1800 सी०सी० से ऊपर इंजिन क्षमता वाले ट्रैक्टरों और ट्रैक्टरों पर कुल उत्पाद-शुल्क क्रमशः 17.25 प्रतिशत और 23 प्रतिशत लगता है। मैं उन पर उत्पाद-शुल्क को कम करके क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

127. मेरे पास वस्त्रोद्योग के लिए उत्पाद-शुल्क-रियायतों का एक पैकेज है। कृषि के बाद, देश में रोजगार देने का यह सबसे बड़ा माध्यम है। अन्य किस्म के किसी भी यार्न की तुलना में पोलिएस्टर और नाइलॉन फिलामेंट पर वर्तमान उत्पाद-शुल्क दर ऊँची हैं। फाइबर और यार्न के संश्लिष्ट (सिंथेटिक) क्षेत्र में पर्याप्त क्षमताओं की स्थापना की गई है। आम आदमी की पहुंच में सिंथेटिक कपड़ों को लाने की दीर्घावधिक नीति के एक भाग के रूप में मैं महसूस

गता है कि इस क्षेत्र में उत्पाद-शुल्क की दरों को कम किए जाने की आवश्यकता है। अतः मैं पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 80.60 रुपये प्रति किलोग्राम से कम करके 69 रुपये प्रति किलोग्राम और नाइलॉन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 71.50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम करके 57.50 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर पर उत्पाद-शुल्क को 13.65 रुपये प्रति किलोग्राम से कम करके 12.65 रुपये प्रति किलोग्राम और विस्कोस स्टेपल फाइबर पर उत्पाद-शुल्क को 15.60 रुपये प्रति किलोग्राम से कम करके 14.95 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं पोलिप्रोपिलिन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 32.50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम करके 28.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे पहले मैं एक्रिलिक स्टेपल फाइबर पर उत्पाद-शुल्क को 15.60 रुपये से कम करके 14.95 रुपये प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

128. स्वास्थ्य देख-रेख पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं निर्दिष्ट थोक (बल्क) औषधियों पर आयात-शुल्क को 110 प्रतिशत या 80 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं निर्दिष्ट औषध मध्यवर्तियों, जिन पर मौजूदा तौर पर 60 प्रतिशत से 110 प्रतिशत तक विभिन्न आयात शुल्क लगाए जाते हैं, के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत की एक समान दर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। होमियोपैथी दवाओं के सम्बन्ध में मैं आयात-शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

129. चिकित्सा-सम्बन्धी उपकरणों का देशीय उत्पादन सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का पात्र है। मौजूदा तौर पर निर्दिष्ट जीवन रक्षक इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा उपकरणों के कुछ कल-मुजों पर आयात शुल्क में पूरी छूट उपलब्ध है। मैं निर्दिष्ट गैर-इलेक्ट्रॉनिक जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण की देशीय प्रक्रिया को तेज करने में सहायता देने के लिए ऐसे कल-मुजों पर भी पूर्ण छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुछ अन्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए अग्रवर्गों के सम्बन्ध में मैं मौजूदा आयात शुल्क को 45 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त इन्हीं करणों से मैं निर्दिष्ट नजर-रक्षक उपकरणों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर उत्पाद-शुल्क को कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

130. मैं फार्मास्यूटिकल उद्योग द्वारा अन्तःशिरा द्रवों की पैकिंग के लिए एसेप्टिक फार्म-फिल-सील मशीनों पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

131. मैंने उत्पाद और सीमा-शुल्कों में परिवर्तन करने के लिए वित्त-विधेयक में भी कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है, जो सामान्यतः समर्थकारी प्रावधान के रूप में हैं और उनका राजस्व की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा, कुछ मौजूदा अधिसूचनाओं में संशोधन करने के प्रस्ताव हैं। मैं सदन का समय बचाने के लिए यहाँ उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ।

132. जैसा कि पारम्परिक रूप से परिकलित किया गया था उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में परिवर्तनों से सम्बन्धित पहले रखे गए प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 2,249 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने की सम्भावना है। लेकिन मुझे आशा है कि शुल्कों में कमी करने सहित सरकार जिन बहुत से कदमों को उठा रही है, उनके परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्क वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी और इसलिए क्षति को इस मद में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के लाभ द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित कर लिया जाएगा। उत्पाद-शुल्कों में राजस्व के निवल घाटे में केन्द्र का हिस्सा 708 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 541 करोड़ रुपये होगा।

133. सीमा-शुल्कों की प्रस्तावित पुनर्संरचना के परिणाम-स्वरूप 3,273 करोड़ रुपये की निवल हानि होती है। यह सम्पूर्ण राजस्व हानि केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी।

134. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों, दोनों की मिलाकर मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप अग्रत्यक्त करों में 4,522 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होती है। केन्द्र के राजस्व में 3,981 करोड़ रुपये और राज्यों के राजस्व में 541 करोड़ रुपये की हानि है। मेरा विश्वास है कि यह एक अस्थायी हानि है और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। मध्यावधि में इस हानि की वृद्धि कुशलता, प्रतिस्पर्धात्मकता और अर्थव्यवस्था के तेज विकास द्वारा पूर्ति कर ली जाएगी।

135. 28 फरवरी, 1993 से सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी बनाने से सम्बन्धित अधिसूचनाओं की प्रतियाँ यथा समय सदन के सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

136. अग्रत्यक्त करों से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों के कारण होने वाले राजस्व घाटे को हिसाब में लेने के बाद वर्ष 1993-94 के लिए बजटीय घाटा 4,314 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 36,959 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

137. खानगीय अग्रत्यक्त महोदय हमारे चारों तरफ विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है, यह एक बाजार के रूप में अधिक एकीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक होता जा रहा है। अन्य विकासशील देश इन चुनौतियों की मुकाबला करने के लिए अपने को सफलतापूर्वक बदल रहे हैं। हम इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सकते, अन्यथा दकियानूसी पूर्वग्रहों और सांस्त्रदायिक विभाजनों में फंसे रहेंगे। निदान स्पष्टतः आर्थिक कार्यालय के कार्य में हमारे लोगों, विशेषकर नवयवकों की

भारी ऊर्जा का उपयोग करने में है। मैंने इस बजट को, आर्थिक और सामाजिक विकास को राष्ट्रीय कार्यसूची पर दृढ़ता से वापस लाने के एक अवसर के रूप में प्रयोग किया है। विश्व को यह दिखाने का एकमात्र रास्ता है कि भारत प्रगति के पथ पर अग्रहित होने वाला राष्ट्र है और सफलता पाने के लिए दृढ़संकल्प है।

138. भारत की नियति विश्व के आर्थिक और राजनीतिक मंच पर एक प्रमुख भूमिका निभाने की है। उसके लिए हमें गरीबों और सुविधावंचितों के लिए गहरी तथा चिरस्थायी चिन्ता करने वाली गतिशील और तेजी से विस्तारित होने वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। हमारे हृदय में संजोए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीति को एक अर्थपूर्ण साधन बनना है। जब राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के सम्बन्ध में कार्रवाई करनी हो तब टकराव या शीत युद्ध के दांवपेचों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें बुद्धिमत्ता, गांभीर्य, उद्देश्य की दृढ़ता और इन सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है।

139. जैसाकि स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व का अंश होता है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें एक सजगृत अर्थव्यवस्था और एक न्यायोचित समाज के निर्माण के लिए इस दैवी क्षमता को जुटाया जा सके। यही एक ऐसी चुनौती है जिसका हमारी राजनीतिक प्रणाली को डटकर सीधा मुकाबला करना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि यह बजट इस अत्यावश्यक कार्य की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करता है।

140. महोदय, मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती जानकी कटपालिया, अवर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1993

F. No. 15(46)—B (D)/93 :—The following is issued for general information :—

BUDGET 1993-94

Speech of Shri Manmohan Singh

Minister of Finance

27th February, 1993

PART A

Sir,

I rise to present the budget for 1993-94.

2. It is now twenty months since our government took office : twenty eventful months in which we have worked ceaselessly to overcome the very difficult economic situation we inherited. In June, 1991, the

economy was in the throes of an unprecedented balance of payments crisis. A savage squeeze had been imposed on imports; international confidence had collapsed; industrial production was falling; and inflation was on the rise.

3. The sense of crisis is now behind us. We have restored a measure of normalcy to our external payments. The annual rate of inflation has been reduced from the peak of 17 per cent in August, 1991 to below 7 per cent. International confidence has been restored. Agriculture has performed well in the current year and industrial production is beginning to recover. The growth of the economy, which had declined to 1.2 per cent in 1991-92, is expected to be around 4 per cent in 1992-93. The economic strategy we have followed, resting on the twin pillars of fiscal discipline and structural reform, has been vindicated by the decisive upturn.

4. Fiscal discipline was necessary because the government had lived for too long beyond its means. The rising fiscal deficits of the Central Government were the root cause of our balance of payments problem, rising prices and high rates of interest. We have made good progress by reducing the fiscal deficit from 8.4 per cent of GDP in 1990-91 to about 5 per cent in the current year.

5. Policies of structural reform aimed at increasing efficiency in resource use and improving our international competitiveness were crucial for providing a lasting solution to the payments crisis. It was necessary to restructure our trade and industrial policies, encourage efficiency through greater domestic competition, allow our producers to have access to imports at reasonable rates of duty, encourage foreign investment and upgradation of technology, and progressively integrate the Indian economy with the world economy. Without these reforms, India would face the certain prospect of entering the 21st century as just about the poorest country in Asia. I am convinced that the Indian people would never tolerate such an outcome. India's natural and human resources entitle us to think in terms of becoming a major powerhouse of the world economy. Our reforms are inspired precisely by this vision.

6. The policy initiatives we have taken do not in any way reduce our commitment to take care of the poor and the disadvantaged. On the contrary, we have taken steps to minimise the burden of adjustment on the poor and working classes. We have disproved those professional prophets of gloom who were predicting millions of people becoming unemployed.

7. When we embarked on this path, we knew that the benefit of our policies would only be seen after three to four years. Patience is therefore essential. Nevertheless, Honourable Members can take comfort that the early results are certainly encouraging. Inflation is down and production is beginning to recover. Fears of being swamped by imports as a consequence of liberalisation have proved to be grossly exaggerated. Despite the virtual removal of import licensing in 1992-93, total imports in 1992-93 in US dollars are likely to be lower than in 1990-91. Although the rupee has been floated for most current account transactions, the market exchange rate has remained relatively sta-

bie. The investment climate has improved considerably. Corporate capital issues by non-government public limited companies in April-October, 1992 were 67 per cent higher than in the same period for the previous year. Loans sanctioned by financial institutions in the first ten months of 1992-93 were 49 per cent higher than in the same period of the previous year. Foreign investors are showing active interest in investment in many sectors, including critical infrastructure sectors such as power and petroleum. Since August 1991 the approvals given for foreign investment proposals upto the end of January amount to an equity investment of \$2.3 billion. These are of course only approvals at this stage and actual flows will take time to materialise, but they certainly indicate a substantial potential for larger investment inflows in the future.

8. Nevertheless, there is no room for complacency. Fiscal imbalances are still large. The efficiency and resource generating capacity of public sector enterprises are still very inadequate. Inflationary expectations have not yet been purged from the system and inflationary pressure could easily build up again if fiscal discipline is relaxed. The economy is still vulnerable to external shocks and loss of confidence. The riots and disturbances in December and January have also taken their toll, by disrupting domestic production and exports and by casting doubts about the stability of our polity and society and our determination to persevere with the difficult task of economic reform. We can ill afford such doubts.

9. The priorities for economic policy, at this critical stage of our economic restructuring are very clear :

- We must continue with the fiscal correction to ensure that inflationary expectations are effectively curbed; to this end, the fiscal deficit both at the Centre and in the States must be further reduced as a percentage of GDP.
- The room for fiscal manoeuvre gained by restraining expenditure over the past two years must be used to give a strong fillip to development expenditure in 1993-94, especially for programmes of poverty alleviation, rural development and the vital social services such as education and health.
- The hesitant industrial recovery must be converted into a strong revival in 1993-94, which can then be followed by a vigorous boom in the last three years of the Eighth plan.
- We must make further progress with our announced strategy of tax reform, moving to a simpler tax system, with moderate rates and much greater focus on compliance.
- We must ensure that our economic strategy gives full support to agriculture which the livelihood and well being of the majority

of our people depend, and also to agro-processing industries, which have a tremendous potential for increasing employment and income in rural areas.

Finally, exports must be made a truly high priority national endeavour so that we can move as quickly as possible to managing the balance of payments without the need for continued exceptional financing from abroad. This is the only meaningful route to self-reliance.

10. The expenditure and tax proposals for 1993-94, which I will be presenting shortly, have been tailored to meet these objectives.

11. Adequate availability of credit at reasonable rates of interest will be critical in converting this year's weak industrial recovery into a strong revival next year. One factor behind the inadequacy of credit for the commercial sector is the pre-emption of a large proportion of banks' resources by the government at below-market rates of interest through the Statutory Liquidity Ratio (SLR). In 1992-93 we began the process of reducing the SLR in order to release a larger volume of resources for commercial lending. Our objective is to reduce the SLR further from an effective average level of about 36 per cent at present to about 25 per cent over the next 3 years. The precise phasing of the reduction will be announced by Reserve Bank of India, taking into account the emerging aggregate monetary and credit situation.

12. The reduction in inflation achieved thus far justifies a reduction in interest rates. Accordingly, the Reserve Bank of India is separately notifying a reduction in the maximum interest rate on bank deposits from 12 per cent to 11 per cent. Simultaneously, the minimum lending rate of 18 per cent on commercial advances is being lowered to 17 per cent. It is my expectation that the lowering of interest rates will help the economic recovery in the coming year. As inflation abates, there will be scope for further reduction in interest rates.

13. No economic strategy can succeed in our country which does not recognise the central role of agriculture in supporting broad-based and equitable development. The government is firmly committed to ensuring that agriculture, agro-processing and rural development are given top priority in the design of economic policy.

14. A major instrument for encouraging agricultural production and making it profitable is the assurance of remunerative prices to the farmers. Procurement prices for the last kharif crop and the forthcoming rabi have been handsomely raised to ensure that farmers are compensated for increases in the cost of inputs. It is also the policy of the Government not to place administrative restrictions on movements of agricultural products within the country. Our farmers must have the full benefit of prices available in the domestic market.

15. Agricultural credit is another critical input for agricultural, and more broadly, rural development. The flow of rural credit from institutional sources is expected to jump from Rs. 13,800 crore during 1992-93 to Rs. 16,500 crore during 1993-94, an increase of 20 per cent. NABARD's investment refinance support to banks will increase by 22 per cent from Rs. 2,300 crore in the current year to Rs. 2,800 crore in 1993-94. Within this total, NABARD has evolved an innovative package of measures to ensure special attention to priority areas. Term loans for minor irrigation will support the sinking of 3.75 lakh wells and installation of 6 lakh pumpsets. The rate of NABARD refinance of bank loans is being increased to 90 per cent in the case of North Eastern States and also of investments in 100 per cent export oriented units in agriculture and allied activities. NABARD will also take up pilot projects for intensive development of rural industries in five selected districts with an outlay of Rs. 125 crore. NABARD is setting up a Venture Capital Fund, with an initial corpus of Rs. 5 crore, to assist new and innovative investments in farm and non-farm sectors, and a Cooperative Development Fund with an initial corpus of Rs. 10 crore to help improve management systems and skills in cooperative banks. In 1993-94, we shall pay special attention to revitalising the agricultural credit system so that it becomes a more effective instrument for increasing capital formation and productivity of agriculture.

16. Our strategy of gradually reducing the high levels of protection to Indian industry and integrating our economy with the world economy, will clearly help Indian agriculture. It will moderate the high industrial prices which the farmers has to pay. It will also ensure a more competitive exchange rate, at which our agricultural and agro-based exports will be much more profitable. I venture to suggest to Honourable Members that in the medium run, these changes will be far more significant in favouring agricultural producers than any programme of special subsidies could ever be.

17. In my Budget speech last year I had indicated that the Government intended to implement the recommendations of the Narasimham Committee on financial sector reform in stages. The securities scam which was discovered in April 1992 has revealed certain weaknesses which add urgency to the need for financial sector reform. A major reform initiated last year was the introduction of new norms for income recognition, and provisioning for bad debts and the prescription of new capital adequacy requirements in line with internationally accepted Basle Committee norms. The new norms will ensure that the books of the banks will reflect their financial position more accurately and in accordance with internationally accepted accounting practices. These changes will improve our ability to evaluate the performance of the banks and will also make for more effective bank supervision.

18. Because of the new norms, however, banks will have to make large provisions amounting to over Rs. 10,000 crore for bad and doubtful advances in their portfolios. As the provisioning norms are being introduced in two stages, the first impact will be felt in the year ending 31 March 1993, with a fur-

ther impact next year. The resulting losses will eat into the capital of the banks, which is already inadequate given the new capital adequacy norms. In order to protect the viability and financial health of the Indian banking system I am making provision for a large capital contribution of Rs. 5,700 crore to the nationalised banks in 1993-94 to meet the gap created by the application of the first stage of the provisioning norms. There will be no immediate net outgo from the budget, as the Government's contribution is in the form of Government bonds; but the interest payment on these bonds, and their ultimate redemption will be a real burden on the budget in future. This is the price we have to pay for having long tolerated management practices in the banks and types of lending which paid inadequate attention to portfolio quality and recoveries. I may add that while undertaking such a large injection of capital into the banks, specific commitments will be required from each bank to ensure that their future management practices ensure a high level of portfolio quality so that the earlier problem does not recur.

19. Even this large injection of capital will only solve the immediate problem. Additional losses will arise because of the second stage of provisioning next year. Besides, the capital adequacy requirements are also being introduced in a phased manner and there will be additional capital needs on this account in 1994-95 and 1995-96. This burden cannot be borne entirely by the budget without eating into scarce resources which are desperately needed for development, especially in the rural areas. Government has, therefore, decided that the State Bank of India, as well as other nationalised banks which are in a position to do so, will be allowed to access the capital markets to raise fresh equity to meet their shortfall in capital requirements over the next three years. The additional capital thus mobilised will help our banks to expand their lending which would otherwise be constrained by capital inadequacy. Government will, continue to retain majority ownership, and therefore effective control, in the public sector banks. Necessary legislation to give effect to this decision will be introduced later in the year.

20. If banks are to make provisions for bad debts, they must also be able to realise the security on their bad debts. At present the legal process for realising bank dues is tortuous, and cases take several years in the courts. Government has, therefore, decided to set up Special Tribunals to expedite legal action by the banks to enforce recoveries. Legislation to this effect will be introduced in the course of the year.

21. The securities scam has also revealed weaknesses in the existing system of supervision of banks. Following the recommendations of the Narasimham Committee, Reserve Bank of India has decided to strengthen its supervisory arrangements by setting up a separate Board for Financial Supervision within the Reserve Bank.

22. Parallel with reforms in the banking system we are vigorously pursuing reforms in the capital markets. We must ensure that trading and settlement take place with speed and transparency under appropriate rules and regulations designed to ensure investor

protection. The Securities and Exchange Board of India, which was given statutory status and powers twelve months ago, has been entrusted with the task of bringing about this transition. As promised in my last Budget speech, the office of the Controller of Capital Issues in the Ministry of Finance has been abolished, and almost all powers under the Securities Contract (Regulations) Act have been delegated or transferred to SEBI.

23. Several important steps have been taken in the current year to reform the capital market. Rules and regulations have been notified to deal with insider trading, the operation of mutual funds, registration of brokers, merchant bankers and other intermediaries. The scheme for allowing Foreign Institutional Investors to invest in the capital markets announced in my last Budget speech has been implemented and a number of approvals given. Several private sector mutual funds have recently been given clearances by SEBI. A company has been incorporated for the establishment of a National Stock Exchange which is expected to operate as a model stock exchange with member brokers all over the country trading in the exchange through modern telecommunication facilities. Proposals are also being considered for the establishment of a centralised depository with a National Clearance and Settlement System.

24. We are determined to ensure that further reforms of the capital market are implemented in the course of 1993-94 so that the capital market can mobilise large funds for investment. On the basis of experience gained, the Government has decided to amend the Securities and Exchange Board of India Act to give SEBI additional powers in order to increase its effectiveness.

25. With reforms underway in the banking sector and in the capital markets, it is necessary to address the need for similar reforms in the insurance industry aimed at introducing a more competitive environment subject to suitable regulation and supervision. I propose to appoint a High Powered Committee to go into these issues in depth and submit its recommendations within six months.

26. In my Budget speech last year, I announced the introduction of a new system of exchange rate management under which a dual exchange rate regime was introduced, and import licensing was eliminated on most items of capital goods, raw materials, intermediates and components. These items became freely importable against foreign exchange purchased in the market. The system has worked fairly well and the market exchange rate has been remarkably stable. The existence of a dual rate, however, hurts exporters and other foreign exchange earners who have to surrender 40 per cent of their earnings at the official rate, getting the benefit of the higher market rate on only 60 per cent. Many exporters have said that this amounts to a tax on exporters of goods and services whose continuation cannot be justified at a time when exports must receive our fullest support. There is merit in this point of view, and the experience of the past year gives ground for confidence that we can unify the exchange rate and still manage the balance of payments with a reasonable degree of stability in the exchange rate. The Government has therefore decided to eliminate the dual rate arrange-

ment. All exporters, as well as other foreign exchange earners such as our workers abroad, will henceforth be allowed to convert 100% of their earnings at the market rate. All imports will also henceforth have to be paid for at the market rate. The details of the new system are being notified separately by Reserve Bank of India. I expect that this will give a major boost to exports, and will further encourage foreign exchange flows into official channels.

27. Several other steps are also being taken to stimulate exports. The Commerce Ministry is reviewing the list of items whose exports are subject to one or other restriction with a view to removing as many restrictions as possible. Reserve Bank of India is taking steps to ensure that adequate credit will be available for exports. Banks have already been asked to ensure that export credit amounts to at least 10% of their total advances. The interest rate on rupee export credit is being reduced by one percentage point. As a further measure of support for exports, the interest tax will be waived in the case of export credit from banks. I will have more to say on incentives for exporters when I come to the tax proposals in the Budget.

28. A new policy towards foreign investment has been an integral part of strategy of modernising the economy, and establishing global linkages which will be of critical importance in the emerging world economy. I have already mentioned that the initiatives taken in this area thus far have yielded encouraging results. I have no doubt that as our reforms proceed and gain momentum, we can expect to attract a substantial share of the private investment that is presently flowing to many developing countries in Asia. The Government has signed the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) convention and we expect to join MIGA formally as soon as membership procedures are completed. Several countries, including the UK, Germany and the United States, have expressed an interest in signing bilateral investment treaties. The Government has indicated a willingness to enter into bilateral negotiations on this issue.

29. Industrial modernisation, and especially the creation of internationally competitive industries, requires a massive expansion of and qualitative improvement in infrastructure. This is especially true of power generation, telecommunications and roads. Traditionally, these areas have been the preserve of the public sector. Substantial expansion of public investment in these areas is certainly necessary. However, the needs of the country are far beyond the capacity of the public sector to deliver in a reasonable time frame. The Government has, therefore, adopted a policy of encouraging private sector involvement and participation in these areas to supplement the efforts being made by the public sector. In order to attract such investment it will be necessary to make changes in policies, procedures and the regulatory framework in these sectors. The Government proposes to make such changes as the need arises.

30. Over the past two years, we have taken several steps to remove unnecessary bureaucratic interference in economic activity in order to create an environ-

ment in which the energies of our people can be harnessed to maximise innovation, production and growth. However, I am constantly told that despite liberalisation at the policy level, our procedures in many areas remain archaic and cumbersome. Many of our laws also need thorough review to bring them in line with the emerging economic environment. The Government has therefore decided that a special review group will be constituted in each Ministry to make a review of existing laws and procedures to identify changes needed in the light of the new policies. I hope the State Governments which have a crucial role to play in promoting development and investment in the new environment will also take similar steps at their end.

31. Let me now turn to the revised estimates for 1992-93.

32. We have tried to maintain strict control over expenditure, but certain increases over the Budget estimates were unavoidable. An additional provision of Rs. 1,500 crore has to be made for food, fertiliser and export subsidies. The additional requirement of food subsidy is because of the delay in increasing issue prices to absorb the impact of higher procurement prices. The higher provision for export subsidy is because of settlement of claims in the pipeline for cash compensatory support and continuance of benefits for deemed exports. In respect of fertilisers the increase is due to the reduction in prices of urea and higher input costs. In addition, I have provided Rs. 340 crore as one-time assistance to farmers for purchase of fertilisers whose prices were decontrolled. Ministry of Home Affairs has to be provided additional funds for meeting security-related expenditure in the wake of disturbed conditions in certain parts of the country. While an assessment of the actual requirements is being made, I have for the present included in the Revised Estimates an additional provision of Rs. 285 crore. If a further provision becomes inescapable, we shall come to the House for the necessary Supplementary Grants. These and other increases have been offset by a reduction of Rs. 1,300 crore in the requirements for loans to States against small savings collections. The decline in small savings collections has been a matter of concern and Government has taken measures to improve the rate of return to the investors. As a consequence, the collections have shown an uptrend in recent months. As a result of all these developments, total non-plan expenditure is higher by Rs. 3,278 crore as compared with the budget estimates.

33. On the plan side, there is an increase in budgetary support for the Central Plan for certain sectors. An additional provision of Rs. 630 crore is being made for the National Renewal Fund, which is a key element in our strategy for economic reforms. Similarly an additional provision of Rs. 250 crore has been made for strengthening schemes in the social sectors such as Health and Family Welfare. The provision for Rural Development is being augmented by Rs. 500 crore.

34. Central assistance to State and Union Territory Plans is being augmented by Rs. 1,228 crore mainly for externally aided projects where the pace

of implementation justifies an allocation larger than in the Budget Estimates.

35. Taking Plan and non-Plan expenditures together, the total provision in the Revised Estimates is Rs. 1,24,726 crores against Rs. 1,19,087 crore in the Budget Estimates.

36. Against these additional expenditures revenue receipts have also been higher because of better collections and higher royalty on offshore crude oil. Capital receipts under market loans and small savings receipts are lower than in the Budget Estimates; but this is offset by the higher receipts from 364-days treasury bills, which is a new instrument designed to develop a market for Government securities.

37. The total receipts in the Revised Estimates are Rs. 1,17,524 crore compared to Rs. 1,13,698 crore in the Budget Estimates. The Budget deficit is estimated at Rs. 7,202 crore and the fiscal deficit for the year is now placed at Rs. 36,722 crore. These figures are somewhat higher than envisaged in the Budget Estimates but within tolerable limits for macro-economic stability.

38. I now turn to the Budget Estimates for 1993-94.

39. The resource constraints facing us last year imposed a tight leash on the development programmes we could finance in 1992-93. The total size of the Central Plan in 1992-93 (BE) was only 12.6 per cent higher than in the previous year. With the improvement in the fiscal situation achieved in the course of 1992-93, and the moderation in inflation, we are now in a position to give a boost to the Plan while ensuring continued improvement in the fiscal deficit. Accordingly, the Central Plan outlay for 1993-94 has been fixed at Rs. 63,936 crore which is almost 32 per cent higher than the figure of Rs. 48,407 crore in 1992-93.

40. The Central Plan will be financed to the extent of Rs. 23,241 crore from budget support which is almost 26 per cent higher than the budget support of Rs. 18,501 crore in 1992-93. The balance of the Central Plan outlay of Rs. 40,695 crore will be met from internal and extra-budgetary resources compared with Rs. 29,906 crore in 1992-93, representing a step-up of 36 per cent. I am providing Rs. 18,010 crore for Central assistance for States and UT Plans in 1993-94 compared to Rs. 16,111 crore in 1992-93. The total budgetary support from the Central Government Budget to the Central and State Plans increases by almost 19 per cent from Rs. 34,612 crore in 1992-93 to Rs. 41,251 crore in 1993-94.

41. The large increase in budget support for the Plan has enabled a substantial step-up in Central Plan programmes in the social sectors and rural development which depend upon budgetary resources. The outlay for the Department of Rural Development next year has been enhanced by a massive 62 per cent to Rs. 5,010 crore. Both employment generation and capital formation in rural areas will receive a major boost. The allocation for the Jawahar Rojgar Yojana is being increased to Rs. 3,306 crore compared with the current year's level of Rs. 2,046 crore. This is

aimed at creating 1100 million mandays of employment. It is proposed to train 3.5 lakh young persons in rural areas under the Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSEM) programme. For the rural water supply programme, the provision has been increased substantially from Rs. 460 crore in 1992-93 to Rs. 740 crore next year. Higher allocations have also been provided for the integrated Rural Development Programme. The programmes of decentralised planning and development will receive a massive stimulus as a result of the strengthening of Panchayati Raj institutions as envisaged in the Constitution (72nd Amendment) Bill 1991.

42. The development of human resources is given high priority in the Eighth Plan; Hon'ble Members are also aware that education is an area which is very close to my heart. I am, therefore, particularly happy to announce that the outlay for education is being increased from Rs. 952 crore to Rs. 1,310 crore, which is a step up of 37.6 per cent. Universal provision of primary education and adult literacy of satisfactory quality, particularly for girls and women, is a prerequisite for the modernisation of the economy and the society. I am happy to inform Honourable Members that our total literacy campaigns are breaking new grounds, and are now being implemented in 182 districts covering approximately 430 lakh adult learners. A new scheme is being launched for the improvement of primary education in educationally backward districts and in districts where the total literacy campaigns have been successful, leading to an enhanced demand for primary education. In these districts, districts specific and population specific plans for achieving universalisation of elementary education are being prepared. Twenty to twenty-five districts out of about 200 educationally backward districts where female literacy is below national average, will be taken up for preparation of district plans in 1993-94. In the sphere of higher and technical education, modernisation and upgradation would receive high priority. Keeping in view the aspirations of the North-Eastern region, the government has decided to set up a university in Nagaland and an Indian Institute of Technology in Assam.

43. For Health, the provision is Rs. 483 crore, which is 60 per cent higher than the level of Rs. 302 crore in the current year's Budget. A major part of the provision will be for national programmes for control of communicable and other diseases. The Family Welfare programme is of overriding national importance; the provision under this head is being stepped up from Rs. 1,000 crore for the current year to Rs. 1,270 crore for the next year. A programme to improve the quality of family planning services in Uttar Pradesh is being launched at a cost of US\$ 325 million, with assistance from USAID. In addition, with the aim of reducing maternal mortality, under the Social Safety Net Scheme, assistance will be provided for improvement of infrastructure at Primary Health Centres in 90 demographically backward districts.

44. The National Commission for Women set up last year is looking into various important issues relating to women. For the integrated child development services the provision is Rs. 474 crore compared

to Rs. 360 crore in the current year. This will enable as to strengthen the infrastructure set up of the scheme. The provision for the Ministry of Welfare has been increased from Rs. 530 crore to Rs. 630 crore. This includes Rs. 73 crore for the liberation and rehabilitation of Safai Karamcharis. A provision of Rs. 247 crore has been made for special Central assistance for Scheduled Castes component plan. The operations of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation and the National Backward Classes Finance and Development Corporation will be further expanded.

45. The Government regards agriculture as a sector of prime importance for the national economy. The budgetary allocation for the plan schemes of the Ministry of Agriculture including Animal Husbandry and Dairying is being increased by 36 per cent from Rs. 1,408 crore to Rs. 1,918 crore. In addition, the bulk of the outlay on agriculture is in the State Plans.

46. The requirements of the infrastructure sectors such as Petroleum and Natural Gas, Power, Telecommunications, Railways and Transport have also not been neglected. Investment programmes in these sectors are implemented through public enterprises or departmentally run commercial undertakings and these organisations are expected to finance their plan outlay through their internal and extra budgetary resources. The plan outlay for Petroleum and Natural Gas has been nearly doubled to Rs. 12,114 crore from the current year's level of Rs. 6,208 crore. The outlay for Power has been increased by 22 per cent from Rs. 5,167 crore in the current year to Rs. 6,269 crore. The outlay for Roads has been stepped up from Rs. 464 crore to Rs. 593 crore. The outlay for Chemicals and Petro-Chemicals has also been stepped up from Rs. 763 crore to Rs. 1,206 crore. The Plan outlay for the Railways has been increased from Rs. 5,700 crore to Rs. 6,900 crore including Rs. 400 crore for the Konkan Railway Corporation Ltd.

47. Turning to non-expenditure, I would like to draw the attention of the House to the tremendous burden of interest payments. The provision for 1993-94 is Rs. 38,000 crore compared with Rs. 32,500 crore in the current year. The high interest burden is due to the rising volume of government debt, which itself reflects the large fiscal deficits, incurred year after year. However, with the reduction in the fiscal deficit and hence in the Government's borrowings, the growth of this item is expected to decelerate sharply by 1995-96.

48. For Defence expenditure the provision have been increased from Rs. 17,500 crore in the current year to Rs. 19,180 crore next year. The requirements on account of fertilisers and export subsidies will be significantly lower reflecting the impact of the measures already taken to rationalise these subsidies. The expenditure on the Farm Loan Waiver scheme will be Rs. 500 crore; with this, the Government's commitment for payment under the scheme will be fulfilled. I am providing Rs. 3,000 crore for food subsidy against Rs. 2,800 crore in the current year. It will be the endeavour of Government to keep the burden of food subsidy at a reasonable level and to ensure at the same time that the vulnerable sections of society are fully protected. Excluding the expenditure on

interest, the provision for other non-plan expenditure in 1993-94 is about Rs. 3,180 crore lower than the Revised Estimates for the current year. As in previous years, no separate provision is being made for additional dearness allowance which may become payable next year. The additional expenditure on this account will have to be absorbed by all Ministries within the approved budget provision.

49. Coming to receipts, gross tax revenues at the existing level of taxation are estimated at Rs. 89,389 crore compared to Rs. 78,782 crore in the current year. States' share of taxes next year is estimated at Rs. 22,590 crore as against Rs. 20,525 crore in the current year's Revised Estimates. I am taking a credit of Rs. 3,700 crore for market borrowings as against the current year's level of Rs. 3,670 crore. External assistance, net of repayments, is estimated at Rs. 6,819 crore as against Rs. 5,374 crore in the current year. Net small savings collections next year are estimated to reach the current year's level of Rs. 5,500 crore despite heavy maturities falling due next year. As in the current year's Revised Estimates, I am taking credit of Rs. 3,500 crore for receipts from disinvestment of equity in public enterprises. Total receipts at the existing levels of taxation are estimated at Rs. 130,990 crore and total expenditure at Rs. 131,323 crore leaving a gap of Rs. 333 crore.

PART B

50. I now turn to the tax proposals for 1993-94.

51. In framing these proposals I have been acutely conscious of the conflicting requirements of comprehensive reform of the tax structure on the one hand, and the need to protect revenues to finance the large increase in the Plan, on the other. Last year significant reforms were made in personal income taxation based on the recommendations of the Chelliah Committee. Reform of corporate taxation was deferred until the detailed recommendations of the Chelliah Committee were received. These have since been received. The Committee has also recently submitted its final report on indirect taxes, recommending significant reduction in customs duties as well as rationalisation and simplification of excise duties.

52. I accept the broad thrust of the Chelliah Committee recommendations on both direct and indirect taxes. We must move as rapidly as possible to a regime of moderate tax rates in direct taxation, which will encourage better compliance especially if supplemented by efforts at broadening of the tax base. We must also move to a regime of low to moderate customs duties which is essential for efficient and competitive industrialisation. Our excise duties should also be simplified with fewer rates and our long term aim should be to move to a Value Added Tax System. However, a nationwide value added tax system cannot be introduced overnight. There has to be a broad agreement among the Centre and the States on the design of such a system. In order to promote informed discussion and debate, I am requesting the National Institute of Public Finance and Policy to prepare the design of a possible value added tax system.

53. Although all the major recommendations of the Chelliah Committee are important, they cannot be implemented immediately for the simple reason that tax reform, which typically involves lower tax rates collected on a broader base, often involves a loss of revenue in the short run. Fiscal experts tell us that the loss of revenue will be made up in the medium term, but there is no guarantee that this will happen immediately, and Finance Ministers have to look after the short term if they want to survive in the medium term. I hope the House will agree with me that a phased transition is needed.

54. A key issue in phasing the transition is whether to do a little on all fronts or to make decisive changes in certain areas, with a clear declaration of progress to be made in other areas in future. I have thought over this matter carefully and I feel that decisive action in critical areas is more important than marginal improvements on all fronts. The most critical area for action at present is customs duties. Despite the adjustments in customs duties in the last two budgets, our duties are still much higher than in most of our competitor countries, especially on capital goods. With these duties, and the resulting high capital costs, our producers will never be able to compete in world markets. Nor can we expect new investment, both domestic and foreign, to flow into areas with export markets in view, if high customs duties make them uncompetitive. Yet it is such investments that we need most at present if we want to reduce our dependence on external assistance. We cannot and must not continue with the approach of setting up industries aimed solely at the domestic market in the belief that replacing imports ipso facto contributes to self reliance, without considering at what cost we are effecting the replacement. In fact, replacement at unduly high cost contributes to inefficient industrialisation, an inability to export and a permanent dependence on external assistance. We must take a bold initiative in this area while taking due care to protect the legitimate concerns of our industry. Normally, the revenue loss from customs duty reduction could have been made up through higher excise duties. However, there are compelling reasons for rationalising and reducing excise duties over a wide range of industries because many of our duties are too high and parts of industry are also suffering from recessionary conditions.

55. In these circumstances, Hon'ble Members will appreciate that I have limited room for manoeuvre in the area of direct taxes. Major reform of the corporate tax structure, along the lines recommended by the Chelliah Committee is undoubtedly desirable. However, for the reasons indicated, it will have to be postponed to the next year.

56. I would like, however, to give a stimulus to new investment in those States in which all the districts are industrially backward. Accordingly, I propose to give a five-year tax holiday, commencing from the year of production, for new industrial undertakings located in all the North-Eastern States, Jammu

& Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, Goa and Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Pondicherry.

57. Electricity is a critical input for the future growth of our economy. I therefore propose to introduce a five-year tax holiday in respect of profits and gains of new industrial undertakings set up anywhere in India for either generation or generation and distribution of power. The five-year tax holiday will begin from the year of generation of power.

58. The five-year tax holiday, in both these cases, will be part of section 80-IA of the Income-tax Act. At the end of the five-year period, these units will be entitled to the existing deduction under section 80-IA for the remaining period.

59. To promote a cleaner and healthier environment, I propose to allow depreciation admissible on plant and machinery relating to environment protection and pollution control at 100 per cent, instead of the existing 40 per cent of capital cost under the Income-tax Rules.

60. Hitherto, our institutions of higher learning have been almost entirely dependent on Government funds. As government funds are limited, we must find ways of funding these institutions from industry. This will also bring them closer to industry and more responsive to its needs. I, therefore, propose to raise the income tax deduction given to contributions to approved universities, institutes of technology, institutes of management and equivalent institutions from 50 per cent at present to 100 per cent.

61. A strong science and technology base is an essential prerequisite for a modern, progressive economy. Indian scientists and technologists have proved, time and again, that they are second to none in the world, given the right work atmosphere, proper motivation and adequate facilities. Indian industry needs to spend a lot more on research and development. In doing so, I would encourage industry to make use of the facilities offered by our national laboratories and research institutes. To that end, I propose to introduce a weighted deduction of 125 per cent of the contribution out of income from business of profession for research programmes in approved national laboratories and institutions carrying out research and development in natural and applied sciences. This weighted deduction will be available only for research programmes determined by the users and the producers of research, and approved by the prescribed authority.

62. I propose to extend the five-year tax holiday under section 10A of the Income-tax Act, at present available to units set up in the Free Trade Zones, to units set up in Software Technology Parks and Electronic Hardware Technology Parks. In July, 1991, I had introduced a 100 per cent deduction for three years in respect of income derived from export of software. Software exports have done well and I propose to extend the concession for one more year i.e. for assessment year 1994-95.

63. Under the scheme for permitting Foreign Institutional Investors in our capital market, we had indicated that such investors would be liable to tax at 20 per cent on investment income and 10 per cent on long term capital gains. I also propose to extend a concessional rate of tax of 30 per cent in respect of short term capital gains for such investors.

64. As I have already mentioned, a substantial reform of personal taxation was carried out last year based on the recommendations of the Chelliah Committee. I propose to leave the rate structure and exemption limit unchanged and make only a few modifications.

65. Last year, because of severe resource constraints, I was compelled to retain the surcharge on personal income above Rs. 1 lakh at 12 per cent. I had hoped to be able to remove the surcharge in the current year but I am constrained to continue with it for one more year. However, I propose to raise the standard deduction from salary income from Rs. 12,000 to Rs. 15,000 and the standard deduction for working women with incomes upto Rs. 75,000 from Rs. 15,000 to Rs. 18,000.

66. In recognition of the hardship to old people in these days of inflation, I had given a tax rebate of 10 per cent last year to senior citizens whose gross total income is below Rs. 50,000. I propose to raise the tax rebate to 20 per cent and further increase the income limit from Rs. 50,000 to Rs. 75,000.

67. Last year, I had announced that a scheme for giving Advance Rulings in respect of transactions involving non-residents would be worked out. The scheme has been drawn up and I am bringing forward legislative proposals for the creation of a statutory authority, headed by a retired Judge of the Supreme Court. I do hope that the scheme will be welcomed by non-residents.

68. I propose to extend the simplified scheme of presumptive taxation introduced last year to small road transport operators operating, hiring or leasing one transport vehicle.

69. Payments made under Voluntary Retirement Schemes to public sector employees were fully exempt from income tax; last year I extended this exemption to private sector employees. I propose now to extend this facility to employees of statutory authorities and local authorities.

70. Recognising the trauma of bringing up a handicapped child, I had, last year increased the deduction permissible for guardians of handicapped dependants under the income-tax law from Rs. 6,000 to Rs. 12,000. I now propose to further raise this deduction to Rs. 15,000. I also propose to allow a deduction in respect of income of handicapped minors clubbed with the income of their parent to the full extent of the child's income upto a maximum of Rs. 20,000.

71. In my first Budget Speech in July, 1991, I had proposed the setting up of the National Foundation for Communal Harmony to provide assistance to the children of families affected by communal riots. The Foundation has since been established under the aegis of the Home Ministry. I now propose to extend the benefit of 100 per cent deduction under section 80G of the Income-tax Act in respect of donations made to the Foundation. I also propose to exempt the income of the National Foundation for Communal Harmony fully from income tax.

72. At present, charitable trusts and institutions have to seek approval every three years from the Commissioner of Income-tax in order that donations to them are eligible for tax exemption. To reduce paper work and simplify the procedure, I propose to increase the maximum period of approval by the Commissioner to five assessment years.

73. I would like to see India gain prominence, not only in the global economy, but also in the world of sports. There are provisions in the Income-tax Act to allow exemption in respect of income of approved sports associations or institutions and to grant 50 per cent deduction in respect of donations made to them. I propose to amend the Rules relating to eligible projects or schemes under section 35AC of the Act to include promotion of sports in such activities. This would provide 100 per cent deduction in respect of spending on approved sports projects and schemes.

74. Last year, I had proposed the setting up of a National Court of Direct Taxes for expeditious settlement of litigation in direct tax matters. The proposal has been examined in detail and I hope soon to bring forward legislation in this regard. In regard to a Direct Taxes Code, the Government will take a final view, taking into account the recommendations of the Chelliah Committee on the subject.

75. The Wealth-tax Act was considerably recast last year and the basis of taxation was shifted from wealth to unproductive assets. There has been persistent demand that a residential dwelling is a universal necessity and should not be subjected to wealth-tax. Hence, I propose to exempt the value of one residential house or part thereof from the levy of wealth-tax.

76. Last year, I had exempted residential houses, motor cars, etc. held as stock-in-trade from the levy of wealth-tax. I now propose to exempt urban land held as stock-in-trade. However, to discourage speculation in the guise of stock-holding, I propose to restrict the exemption to three years beginning from the year in which the land is acquired.

77. The exemption limit for purposes of gift-tax was fixed at Rs. 20,000 some years ago. I agree with the recommendations of the Tax Reforms Committee that this limit needs to be revised and, therefore, propose to raise it to Rs. 30,000.

78. Gifts made by a person to any dependant relative in respect of marriage of the relative is exempt from gift-tax only up to Rs. 10,000, whereas vast expenditures on ostentatious marriage go scot-free. In order to encourage savings and productive

investment, I propose to raise the exemption limit at the time of the marriage of a dependant relative from Rs. 10,000 to Rs. 30,000.

79. As an incentive to the export drive which has to be kept up at all costs, I propose to exempt all banking companies from the levy of Interest-tax on export credit provided by them.

80. The various changes that I have proposed would result in a loss of Rs. 300 crore of which the States' share would be Rs. 194 crore. The amount involved is very small—less than 2 per cent of the gross direct tax collections. I am ignoring it in the expectation that better tax collection would cover this loss.

81. I now turn to the proposals relating to indirect taxes.

82. Since 1973, we have been levying a separate auxiliary duty in addition to the basic customs duty. In order to simplify the tariff structure and the assessment process, I propose to do away with the separate auxiliary duty and merge it with the basic duty.

83. Our first priority in restructuring customs duty should be in the area of capital goods and project imports since these duties affect the incentives for new investment. Last year the duty on projects and general machinery was brought down from 80 per cent to 55 per cent. This is still too high compared with rates in competitor countries and a further reduction is necessary. I, therefore, propose to lower the import duty on projects and general machinery to 35 per cent. Projects in certain priority sectors such as, power, coal mining and petroleum refining currently attract a duty rate of 30 per cent. I propose to reduce the rate to 25 per cent in the case of coal mining and petroleum refining. In view of the special importance of the power sector, the duty on power projects is being reduced to 20 per cent and this rate is also being extended to machinery required for modernisation and renovation of power plants.

84. The House can rest assured that in restructuring duties on capital goods, I have made every effort to protect the legitimate interests of domestic capital goods industry. We have had extensive discussions with various Ministries as well as representatives of concerned industries. In order to ensure that lower duties on imported machinery do not hurt the domestic capital goods industry, it is necessary to lower the import duty on components, to enable our manufacturers to compete effectively. I therefore, propose to reduce to 25 per cent the duty on components of general machinery which presently is either 40 per cent or 35 per cent. In order, however, to ensure that domestic industries producing such components are not adversely affected, I propose to impose countervailing duty on such components at 10 per cent with full facility of set-off under MODVAT.

85. At present there are a number of other capital goods, including various types of machine tools, which attract different rates of duty in the range of 60 per cent to 110 per cent. There are also instruments

which attract duties varying from 40 per cent to 110 per cent. I propose to rationalise this structure into three duty rate slots, viz., 40 per cent, 60 per cent and 80 per cent. The rationalisation involves generally a duty reduction between 20 to 30 percentage points. Consequential reduction is being made in the rates of duty on specified parts and components.

86. Hand-operated tools are capital goods for artisans and skilled workers and currently attract duties varying from 40 per cent to 110 per cent. I propose to prescribe a uniform rate of 40 per cent for all these tools.

87. The logic of reduction duties on capital goods requires lowering of duties on metals and metal goods as well, as these are the basic raw materials of the domestic capital goods industry. Accordingly, to help domestic producers, I propose to lower the customs duty rates on ferrous metals by 10 to 20 percentage points in most cases. In line with these changes the import duty on steel scrap is being refixed at 15 per cent. The import duty on specified refractory raw materials is being reduced to 30 per cent. Turning to non-ferrous metals, I propose to reduce the duty rates by 10 to 55 percentage points in most cases. The resulting rates on unwrought and unalloyed forms will vary from 25 per cent to 50 per cent and on wrought forms from 70 per cent to 80 per cent.

88. The duty structure for chemicals is characterised by a multiplicity of rates and many irrationalities. Input duties are often out of line with duties on finished products. I, therefore, propose to restructure the duty rates on chemicals with a view to significantly lowering duty rates at the upper end and also ensuring that the duty rates on inputs are not generally higher than the duty on end products. The present duty rates on basic feed-stocks such as, ethylene, propylene, butadiene, benzene, styrene and ethylene dichloride vary between 25 per cent and 80 per cent. These rates are being replaced by a uniform low duty rate of 15 per cent. The duties on xylenes, paraxylene, toluene, acrylonitrile and cumene are being reduced to 40 per cent. The duties on DMT, PTA and MEG which represent a higher stage of production, are being reduced and unified at 70 per cent. In the case of caprolactum, however, the duty is being increased from 50 per cent to 60 per cent, in order to adequately protect the interest of the domestic units.

89. The electronics industry has the potential of becoming a world class industry contributing to our export effort and to employment generation, I propose to take up this challenge. The rates of duty on project imports and on specified capital goods for electronics attract duty at either 30 per cent or 50 per cent at present. I propose to reduce these rates to a uniform rate of 25 per cent. The import duties on raw materials, piece-parts and components at present are levied at 40 per cent, 60 per cent and 80 per cent. These rates are being reduced to 20 per cent, 35 per cent and 50 per cent, respectively. The import duty on specified raw materials for the manufacture of optical fibre cables is being drastically reduced from 90 per cent to 20 per cent in recognition of the urgency of extending and modernising the telecom sector.

90. In order to strengthen our export capability in existing export-thrust areas such as textiles, leather, marine products, gems and jewellery, etc., where we have a comparative advantage, I propose to reduce the import duty on specified capital goods for these sectors from 40 per cent to 25 per cent. In addition, certain recommendations have been made by the Groups on Extreme Focus items for export for augmenting the export potential of certain sectors such as food processing, horticulture and floricultural industries. Accordingly, the import duty on specified items for these sectors is being reduced to 25 per cent.

91. The ship-breaking industry is employment intensive and an important source of raw materials for the secondary sector of our steel industry. In order to encourage the growth of this industry, I propose to prescribe a lower merged duty of customs at 5 per cent ad valorem. The ferrous materials obtained from breaking up of such ships etc. which are presently subject to excise duty are being fully exempted.

92. Our film industry is one of the largest in the world in terms of the footage of films produced. Although it has achieved this status without much need for incentives, it is now facing greater competition from the electronic media, and deserves some special encouragement. I, therefore, propose to reduce the duties on jumbo rolls of cine positive films from 55 per cent to 25 per cent and on finished cine film rolls from about 65 per cent to 40 per cent. I also propose to reduce the duty on negative cine films from about 35 per cent to 25 per cent.

93. In order to encourage the development of non-conventional energy sources, especially solar energy, the import duty on specified raw materials and items of this industry is being reduced by 15 to 20 percentage points. In respect of wind-operated electricity generators I propose to reduce the import duty from 40 per cent to 25 per cent.

94. As a gesture of goodwill towards Bangladesh, I propose to fully exempt the famous Jamdane saris from payment of import duties. Small-scale units, eligible for excise duty exemption for clearances to domestic area at present required to pay excise duty on goods exported by them to Nepal and Bhutan. I propose to exempt these from this levy. I hope these steps will make a contribution towards trade with SAARC countries.

95. At present, accredited press cameramen have the facility of importing photographic equipment free of duty upto a limit of Rs. 60,000 but no such facility is available to other journalists to import specialised equipment such as, laptop computers, personal computers, personal computers, fax machines and typewriters. I have often wondered whether this explains why my photographs in the Press are better than the editorial comments! As a measure of my commitment to encourage modern technology in Indian journalism, and in recognition of the sterling role played by our Pressmen in creating a wider appreciation of issues of economic reform in the country. I propose to allow accredited journalists also a one time facility to import such equipment duty free upto a value of Rs. 60,000.

96. The duty rate on certain specified items of baggage was recently reduced from 255% to 150%. As a measure of simplification, I propose to reduce the general baggage rate itself from 255% to 150%.

97. In line with these reductions in import duties for individual sectors, and keeping in mind the present exchange rate, there is scope for reduction in the maximum rate of duty on all goods. Accordingly I propose to reduce the maximum rate from 110% to 85% except for a few items including passenger baggage and alcoholic beverages.

98. I am aware that Honourable Members will be concerned that lowering of import duties and import liberalisation may put too much pressure on our industry and make it vulnerable to unfair competition and dumping. I would like to assure Honourable Members that these issues have been carefully considered and the proposed changes will not put undue pressure on industry. The change in the exchange rate over the past two years has created considerable room for duty reduction without hurting domestic industry. Besides, I am also reducing duties on raw materials and inputs which will help to reduce cost for our producers, enabling them to compete more effectively. Even with these changes, duties on finished products will be well above the long term structure recommended by the Chelliah Committee. We can move to that goal in phases over the next few years. As for unfair competition through dumping, our anti-dumping laws are already operational and action under these laws will be taken expeditiously whenever it is needed. I may mention that provisional action has recently been taken in one case.

99. In last year's Budget export duties had been imposed on iron ore and unpolished granite. Certain difficulties faced by these sectors have since been brought to my notice. I, therefore, propose to withdraw the export duty on iron ore and unpolished granite.

100. I turn now to my proposals relating to excise duties. These are guided by the need to simplify the rate structure, to give some relief on articles of mass consumption, help the domestic capital goods industry so as to increase its competitiveness and also reduce capital costs, assist industries suffering from depressed demand conditions, and to provide relief to small-scale industry.

101. A surcharge by way of special excise duty has been levied since 1988, and the rate is currently 15% of the basic excise duty. As a measure of simplification, I propose to merge the special excise duty with the basic excise duty rates while also rationalising the resulting duty rates.

102. I propose to give some relief from taxation on a large number of articles of mass consumption as a measure of protection to the common people, who have been hard hit by inflation. Coffee, tea and instant tea are being fully exempted from excise duty. I also propose to reduce excise duty on vanaspati from Rs. 1900 to Rs. 1500 per metric ton. I propose to fully exempt footwear made by units under KVIC as well as those run with cash assistance received under

the integrated Rural Development Programme, irrespective of the value limit. In respect of footwear manufactured by other units, I propose to enhance the present value limit for the purpose of exemption from Rs. 75 to Rs. 125 per pair. I also propose to reduce the excise duty :

- on evaporative coolers from 23% to 10%;
- on electric fans from 17.25% to 10%.
- on specified domestic electrical appliances from 23 per cent to 15 per cent;
- on dry cell batteries from 34.5 per cent to 25 per cent;
- on printing and writing ink from 17.25 per cent to 10 per cent;
- on radio sets from 23 per cent to 10 per cent;
- on tooth powder from 17.25 per cent to 10 per cent;
- on noodles and roasted cereals from 17.25 per cent to 10 per cent;
- on biscuit from 11.5 per cent to 7.5 per cent;
- on plastic moulded luggage from 34.5 per cent to 25 per cent;
- on mattresses and bedding articles of cellular rubber from 69 per cent to 30 per cent.

103. At present the excise duty on capital goods and instruments varies from 11.5 per cent to 23 per cent. In order to lower capital costs and stimulate investment, I propose to reduce the excise duty on a large number of capital goods and instruments to a uniform rate of 10 per cent. For the power sector, I am proposing an even lower rate of 5 per cent.

104. Revival of industrial growth is a key element in the strategy for 1993-94. Sectors such as the automotive sector, television and the refrigeration and air-conditioning industries are currently suffering from recession. Workers employed in these industries face an uncertain future. Revenue prospects will also suffer if the present trend is not reversed. I, therefore, propose to provide a significant relief to these industries by way of reduced incidence of excise duties. I expect them to respond positively to this stimulus.

105. In order to encourage the public transport sector, I propose to reduce excise duty from 23 per cent to 15 per cent on non-petrol driven commercial vehicles for carrying goods and passengers. Correspondingly, the excise duty on the chassis of such vehicles will also stand reduced to 15 per cent. I also propose to fully exempt excise duty on body-building on chassis of buses and similar passenger vehicles. The excise duty on three-wheelers is being reduced from 23 per cent to 15 per cent. I also propose to reduce the excise duty on motor cars from 55 per cent to 40 per cent.

106. I propose to reduce the specific excise duty on colour television sets from rates at present varying from Rs. 1925 to Rs. 4785 per set to rates varying from Rs. 1250 to Rs. 2200 per set.

107. The rates of excise duty on refrigerators presently vary from Rs. 575 to Rs. 5750 per refrigerator depending on their capacity. I propose to reduce the rates to Rs. 400 to Rs. 3500 per refrigerator. Other refrigerating appliances, including those used for cold storage in the agriculture sector currently attract an ad valorem duty of 69 per cent. This is far too high as it affects the growth of food processing and preservation industries. I, therefore, propose to reduce the duty to 20 per cent. I propose to reduce excise duty on air-conditioners from rates varying from Rs. 13800 to Rs. 85100 per unit at present to rates varying from Rs. 7000 to Rs. 70000 per unit depending on its capacity. In respect of compressors for air-conditioner of capacity not exceeding 7.5 tonnes, I propose to reduce the excise duty from Rs. 6900 to Rs. 5500 per compressor.

108. I propose to reduce the excise duty on bulk plastic resins such as low and high density polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, etc. from 46 per cent to 35 per cent. This measure will benefit small-scale units manufacturing plastic products.

109. Metals are the basic raw materials of industry and the Tax Reforms Committee has suggested reduction of excise duty in this category. I, therefore, propose to rationalise the existing duty structure on metals. On ferrous metals, the ad valorem rates generally vary between 11.5 per cent and 23 per cent. I propose to rationalise the structure into two slabs 12.5 per cent and 15 per cent. Aluminium has duty rates ranging from 23 per cent to 40.25 per cent. I propose to replace these rates by a uniform rate of 25 per cent. Other non ferrous metals like copper, zinc, lead etc. attract duty rates varying from 11.5 per cent to 34.5 per cent. I am proposing a uniform duty of 15 per cent for these. Certain ferrous materials are still subjected to specific rates of duty. I have proposed some upward adjustment in these rates taking into account the price increase since last year.

110. As a measure of environment protection, and in order to save wood, I propose to reduce the excise duty on plywood from 34.5 per cent to 20 per cent. I also propose to include pulp made from rice and wheat straws in the scheme of full excise duty exemption for production of writing and printing paper and uncoated kraft paper containing not less than 75 per cent of pulp made from bagasse, jute, etc. This will widen the scope for using non-conventional raw materials in the manufacture of paper.

111. Currently, excise duty is being levied on mechanised, semi-mechanised, ~~non-mechanised~~ and cottage sectors of the match industry at Rs. 3.15, Rs. 2.10, Rs. 1.75 and Re. 0.75 per hundred boxes respectively. The Government of Tamil Nadu has brought to my notice certain difficulties faced by this industry and also certain anomalies in the structure. Accepting this suggestion, I propose to reduce the rates to Rs. 2.40, Rs. 1.25, Re. 1.00 and Re. 0.50 respectively and also to restrict the existing concessions in the cottage sector only to units which are registered co-operative societies or recognised by KVIC or the State KVIB.

112. The excise duty on cosmetics and everyday toilet preparation such as, talcum powder shampoos, face creams, shaving creams, etc. is very high at 120.75 per cent. These items are now being increasingly used by a wide section of the people for personal care. I

have received several representations from the trade, consumers and women's organisations for reduction of excise duty. I have also received complaints regarding the growth of spurious products and other abuses related to the evasion of this very high duty. I, therefore, propose to reduce the excise duty on cosmetics and toilet preparations from 120.75% to 70%.

113. I propose a marginal upward revision in the specific rates of excise duties levied on tyres, tubes and flaps.

114. I also propose to revise upwards the specific rates of excise duty on molasses from Rs. 172.50 to Rs. 200 per tonne.

115. The small scale sector has been a source of strength to Indian industry and a nursery for new entrepreneurship. The central excise duty exemption scheme for this sector has contributed significantly to its development alongwith other measures taken by the Central and State Governments. I propose to simplify the scheme and restructure it to give additional incentives to the smaller units and at the same time respond to certain recommendations of the Estimates Committee and the Public Accounts Committee.

116. I propose to enhance the limit for exemption registration from Rs. 7.5 lakh at present to Rs. 10 lakh. This will free a large number of the smaller units from the necessity of registration, and at the same time enable the tax authorities to devote greater attention to the comparatively larger units. At present, excise duty is completely exempted from the first Rs. 20 lakh of turnover for units producing goods under one chapter of the excise tariff, and the limit is Rs. 30 lakh if the goods produced are under more than one chapter of the tariff. I propose to enhance the duty exemption limit to Rs. 30 lakh for all units. This should benefit a large number of units in the lower segment of the small-scale sector.

117. As part of the restructuring, I feel that the larger units in this sector can contribute a little more to the exchequer. At present, the excise duty payable above the zero duty limit and upto Rs. 75 lakh is normal duty minus 10 percentage points, subject to a minimum of 5% ad valorem. I proposed to retain this for clearance upto Rs. 50 lakh in a financial year. For clearances beyond Rs. 50 lakh and upto Rs. 75 lakh, the concessional rate will be normal duty minus 5 percentage points, subject to a minimum of 5% ad valorem.

118. At present, buyers of goods from small-scale manufacturers, get a notional credit under MODVAT which is 5 percentage points more than the central excise duty actually paid by the latter. The Public Accounts Committee has found certain irregularities in the operation of this facility. The Tax Reforms Committee has also not favoured continuance of this special dispensation, which essentially helps the large scale user industry. I, therefore, propose to withdraw the higher notional credit which the buyers of goods produced by the small-scale units are getting at present. They will receive MODVAT credit only on the basis of duty actually paid.

119. In respect of cosmetics and refrigerators and air-conditioning appliances, I propose to liberalise the excise duty concessions for the small-scale sector having regard to price escalation over the years. I propose to extend full exemption in respect of clear-

ances from Rs. 5 lakh at present to Rs. 15 lakh. Thereafter, clearances upto Rs. 30 lakh in a financial year would attract 50% of the normal duty. Clearances above Rs. 30 lakh in a financial year will attract normal duty. The liberalise scheme of exemption will be available only to those units whose value of clearances does not exceed Rs. 50 lakh in a financial year.

120. All the proposed changes in the small-scale sector will take effect from 1st April, 1993.

121. I now turn to certain proposals relating to agriculture, textiles and health sectors, covering both customs and excise duties.

122. Agriculture is the key to our economic growth, and deserves special fiscal incentives aimed at modernisation and diversification of this sector. I propose to reduce the import duty on various items of machinery used for agriculture, horticulture, forestry, poultry-keeping, etc. from 55% to 25%. I propose to reduce the import duty on rice transplanters from 40% to 15%. I also propose to reduce the import duty on grand parent poultry stocks from 105% to 40%. The import duty on certain amino acids is proposed to be reduced from 65% to 15%.

123. In respect of out board motors used for fishing, I propose to reduce the import duty from 40% to 15%.

124. I propose to reduce the import duty on specific pesticides from 110% to 75%. The import duty on certain pesticide intermediates is being reduced from rates ranging between 65% and 110% to 50%.

125. I propose to reduce the import duty on specified goods for horticulture and green houses to 25%.

126. At present, tractors of engine capacity above 1800cc and trailers attract a total excise duty of 17.25% and 23% respectively. I propose to reduce the excise duty on them to 10 per cent and 15 per cent respectively.

127. I have a package of excise duty concessions for the textile industry. Next to agriculture, it is the largest employer in the country. The present excise duty rates on polyester and nylon filament yarn are higher as compared to other types of yarn. Substantial capacities have been set up in the synthetic sector of fibre and yarn. As part of a long term policy of bringing synthetic fabrics within the reach of the common man, I feel there is a need to reduce the excise duty rates in this sector. Hence, I propose to reduce the excise duty on polyester filament yarn from Rs. 80.60 to Rs. 69 per kg. and on nylon filament yarn from Rs. 71.50 to Rs. 57.50 per kg. I also propose to reduce excise duty on polyester staple fibre from Rs. 13.65 to Rs. 12.65 per kg. and on viscose staple fibre from Rs. 15.60 to Rs. 14.95 per kg. On polypropylene filament yarn, I propose to reduce the excise duty from Rs. 32.50 to Rs. 28.75 per kg. I further propose to reduce excise duty on acrylic staple fibre from Rs. 15.60 to Rs. 14.95 per kg.

128. Health-care deserves special treatment. I propose to reduce import duty on specified bulk drugs at 110 per cent or 80 per cent to 25 per cent.

I also propose to fix a uniform rate of 50 per cent on specified drug intermediates which currently attract import duties varying from 60 per cent to 110 per cent. In respect of homoeopathic medicines, I propose to reduce import duty from 40 per cent to 25 per cent.

129. Indigenous manufacture of medical equipment deserves all encouragement. At present, full exemption from import duty is available to certain parts of specified life saving electronic medical equipments. To help in accelerating the indigenisation process, I propose to extend full exemption to such parts for the manufacture of specified non-electronic life-saving medical equipments also. In respect of components for the manufacture of certain other medical equipments, I propose to reduce import duty from 45 per cent and 25 per cent at present to 15 per cent. Further, for the same reason, I propose to fully exempt specified sight-saving equipments from excise duty and to lower excise duty on some medical equipments to 10%.

130. I propose to reduce the import duty on aseptic form-fill-seal machines for packing intravenous fluids by the pharmaceutical industry from 40 per cent to 15 per cent.

131. I have also proposed certain amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the excise and customs tariffs which are generally in the nature of enabling provisions and have no revenue significance. Besides, there are proposals for amendment of some of the existing notifications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them.

132. The proposal in regard to changes in the excise duties outlined above are likely to result in a revenue loss of Rs. 2249 crore as conventionally calculated. However, I expect that as a result of the many steps that the Government is taking, including the duty reductions, the production of excisable goods will go up, and the loss will therefore be partially offset by a gain of about Rs. 1000 crore on this account. Out of the net loss of revenue in excise duties the Centre's share will be Rs. 708 crore and that of States Rs. 541 crore.

133. The proposed restructuring of customs duties results in a net loss of Rs. 3273 crore. This revenue loss will be entirely borne by the Centre.

134. The net impact of my proposals on customs and excise duties taken together amount to a revenue loss of Rs. 4522 crore on indirect taxes. The impact on the Centre's revenue is a loss of Rs. 3981 crore and that on States' is Rs. 541 crore. I believe this is a temporary loss and is necessary to impart a new dynamism to India's economy. In the medium term, this loss will be more than made up by increased efficiency, competitiveness and faster growth of the economy.

135. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties effective from the 28th February, 1993 will be laid on the Table of the House in due course.

136. Taking into account the revenue loss arising from my proposals relating to indirect taxes the budget deficit for 1993-94 is estimated at Rs. 4314 crore and the fiscal deficit at Rs. 36,959 crore.

137. Mr. Speaker, Sir, the world around us is changing very rapidly, becoming more integrated as a market place and also more competitive. Other developing countries are successfully transforming themselves to meet these challenges. We cannot afford to stay out of this process, appearing to be absorbed with obscurantist preoccupations and sectarian divisions. The solution lies precisely in harnessing the considerable energies of our people, especially the young, to the exciting task of economic rejuvenation. I have used this Budget as an opportunity to put economic and social development firmly back on the national agenda. This is the only way to show the world that India is a nation on the move and is determined to succeed.

138. It is India's destiny to be a major player on the global economic and political scene. For that we

need a vibrant and rapidly expanding economy with deep and abiding concern for the poor and the under-privileged. Politics has to be a purposeful instrument for realising our cherished goals. There is no scope for confrontation or cold war tactics when it comes to dealing with the nation's social and economic objectives. We need wisdom, sobriety, firmness of purpose and above all national unity.

139. As Swamy Vivekananda used to say there is an element of divinity in each human being. We have to create an environment in which this divine potentiality can be mobilised for building a strong economy and a just society. This is the challenge that our political system must face squarely. I venture to think that this budget focusses the nation's attention on this imperative task.

140. Sir, I commend the Budget to this august House.

SMT. JANAKI KATHPALIA, Addl. Secy. (Budget)